04 - भारतीय भाषाओं के सम्मान में है भाषा विवाद का हल

05 - लंबे लिव इन रिलेशन के बाद दुष्कर्म का आरोप गलत

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 17 मार्च, 2025

06 - तापी सरोवर से हटाई जाएंगी 17 दुकाने

07 - आखिर पूजापाठ का सहारा क्यों ले रहे हैं शासकीय कर्मचारी?

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 187, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

पहली बात

'मिस्टर इंडिया:' जरूरी नहीं कि खुश हुआ 'मोगेम्बो' फिर नाराज न हो?

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

मात्र तीन महिने पुराने शासन-काल ट्रम्प 2.0 के दरम्यान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कूटनीतिक-कौतुक के अजीबोगरीब पैकेज से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कौतूहल से भर दिया है। अंतरराष्ट्रीय-संबंधों में शांति वार्ता, व्यापार, युद्ध, अर्थ-व्यवस्था, संस्कृति,-पर्यावरण और मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों को कूटनीति के पेशेवर निराकरण और निवारण के लिए स्थापित परम्परागत राजनयिक संवाद के शालीन, शांत, समन्वित तरीकों से इतर राष्ट्रपति ट्रम्प का अंदाज हैरतअंगेज है। 'अंतरराष्ट्रीय-तैराकी' में ट्रम्प का अंदाज 'हर ट्रैक' पर 'फ्री-स्टाइल' तैराक की तरह तैरने वाला है। ट्रम्प की स्टाइल पर खुद अमेरिकी ही हैरत में हैं।

राष्ट्राध्यक्षों के परस्पर हितों के संवाद में निर्धारित राजनयिक पहल अनौपचारिक कूटनीति, ट्रैक-2 कूटनीति, निवारक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति, सॉफ्ट-पावर, मौद्रिक-कूटनीति, तोपवाली नाव कूटनीति, तुष्टिकरण और परमाणु कूटनीति जैसे सेगमेंट में बंटी होती है। सब कुछ समझदारी और समन्वय के धरातल पर होता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में तोपवाली नाव यानी शक्ति के आधार पर तोलमोल की कूटनीतिक शैली से परहेज किया जाता है। राजनयिक संवादों के जरिए राष्ट्रीय अथवा वैश्विक हितों के लिए निर्धारित कूटनीतिक मंचों के असफल होने के बाद ही तोपवाली नाव यानी शक्ति के आधार पर फैसले लिए जाते हैं।

अमेरिका के संदर्भ में अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए वह पावर का इस्तेमाल करे। लेकिन 'हर ट्रैक' पर डोनाल्ड ट्रम्प की 'फ्री-स्टाइल' तैराकी से भारत सहित कई मित्र देश असमंजस में हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का यह नया राजनीतिक अवतार सैंतीस साल पहले 1987 में बनी हिंदी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के पात्र 'मोगेम्बो' की तरह है, जिसकी खुशियों की चाहत का सिलसिला कभी भी खत्म ही नहीं होता था। फिल्म में 'मोगेम्बो' खलनायक था, लेकिन ट्रेलर में 'मोगेम्बो' का भावार्थ 'सबसे महान' बताया गया था। सैंतीस साल बीत जाने के बाद भी 'मिस्टर इंडिया' का डॉयलॉग 'मोगेम्बो खुश हुआ' आज भी प्रचलन में है। राजनीतिक, सामाजिक और सामुदायिक अवसरों पर अलग-अलग मुद्राओं में यह डॉयलॉग आज भी दोहराया जाता है।

फिल्म में 'मोगेम्बो' को 'खुश रखना' सबसे कठिन काम था। उसकी हसरतें बेपनाह थीं। मौत उसके लिए खुशियों का सबब थी, किसी की अस्मत उसके लिए खिलौना थी। मोगेम्बो की तरह डोनाल्ड ट्रम्प की ख्वाहिशें बेपनाह हैं। वो दुनिया के स्वतंत्र मुल्क कनाडा को अपना राज्य बनाना चाहते हैं। ट्रम्प गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। चाहते हैं कि गाजा पट्टी में रहने वाले बीस लाख बाशिंदे जार्डन, मिस्र जैसे अरब मुल्कों में भेज दिए जाएं। ट्रम्प की कल्पना है कि गाजा में दुनिया भर के लोग रहें। उन्हें लगता है कि वो गाजा को कल्पनातीत ऐसे अंतरराष्ट्रीय मनोरम स्थान में तब्दील कर देंगे, जहां सब लोग रहना चाहेंगे। गाजा पट्टी में अकल्पनीय संभावनाएं मौजूद हैं। ट्रंप का रूख अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नजरअंदाज करता है, लेकिन वो गंभीर हैं। पनामा नहर पर कब्जे को लेकर भी वह गंभीर है। कनाड़ा, गाजा पट्टी या पनामा नहर पर कब्जे जैसे कई फितूर उनके दिमाग में पल रहे हैं।

फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में 'मोगेम्बो' खून-खराबे और तस्करी के लिए भारत को बेचना चाहता था। फिल्म की स्क्रिप्ट में 'मिस्टर इंडिया' नाम का पात्र 'मोगेम्बो' की साजिशों को नाकाम करता है। स्क्रिप्ट में 'मिस्टर इंडिया' की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 'मोगेम्बो की तरह डोनाल्ड ट्रम्प भी भारतीय आयात-निर्यात के संसाधनों में सेंध लगाने पर उतारू हैं।

अक्टूबर, 2024 में अपने चुनाव अभियान के एक भाषण में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि दुनिया की किसी भी डिक्शनरी के तमाम शब्दों में उनका सबसे ज्यादा प्रिय शब्द 'टैरिफ' है। इसी टैरिफ का इस्तेमाल करके वो अमेरिका के लिए एकतरफा मुनाफाखोरी की इबारत लिखना चाहते हैं। भारत वाणिज्यिक और व्यापारिक परिक्षेत्र विभिन्न इलाकों में सौदेबाजी के उस मुकाम पर खड़ा है, जहां एक ओर कुंआ तो दूसरी तरफ खाई हैं। इसे स्वीकारना आत्मघाती हो सकता है।

जबकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित भारत का बड़ा तबका मुतमईन था कि ट्रम्प 2.0 के दौरान ट्रम्प से उनकी दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन ट्रम्प के औचक रवैय्ये ने भारत की उम्मीदों पर कुठाराघात सा किया है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि अमेरिका अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखता है। इसकी प्रतिपूर्ति में वह कुछ भी कर सकता है। स्वार्थों की इस लड़ाई में अमेरिका भारत को हाशिए पर ढकेलना चाहता है।

ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में जिस विदेश नीति का ऐलान किया है, वो एक बार फिर से दूसरे देशों पर कब्जा करने और अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक करने का संकेत है। ट्रम्प ने सैन्य ताकत के बल पर पनामा नहर और ग्रीन लैण्ड पर कब्जा करने की धमकी दी है। पहले उन्होंने ग्रीन लैण्ड को खरीदने की पेशकश की थी। विदेश नीति के संदर्भ में ट्रम्प के ऐलानों में अन्य देशों और अमरीकी प्रभाव-क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की नीयत है। यूक्रेन से उसकी सौदेबाजी का मुख्य एजेण्डा रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध विराम से ज्यादा उसके दुर्लभ, दुरूह और बिरले प्राकृतिक खनिज संपदा पर कब्जा करना ही है।

भारत को ट्रम्प के चक्रव्यूहों से सावधान रहने की जरूरत है। कूटनीति में दोस्ती और रिश्ते काफी नीचे सरक जाते हैं। मीडिया में ऐसी सुर्खियां महज धुंध ही पैदा करती हैं। ट्रम्प की महज यह बात तालियां पीटने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उनकी नजर में मोदी चालाक 'निगोशियटर' हैं। मोदी की कुर्सी सरकाना भी महज व्यवसायिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इतिहास गवाह है कि दोस्ती के मामलों में अमेरिका सबसे ज्यादा अविश्वसनीय देश है। यदि वह 'मोगेम्बो' के रूप में भारत के निर्यात और कृषि उत्पादों पर कहर ढहाने पर आमादा है तो 'मिस्टर इंडिया' के रूप में देश के प्रधानमंत्री को भी उतनी चतुराई से उन्हें रोकना होगा। वैसे विभिन्न स्तर पर कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए लंबी ढील देकर प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक चतुराई का परिचय दिया है। इस बीच दुनिया की प्रतिक्रियाएँ और दबाव के परिणाम भी सामने आने लगेंगे।

भारत ने कई मामलों मे लचीलापन दिखाया है। लेकिन ट्रम्प की सार्वजनिक भाषा कूटनीति की उन मर्यादाओं का पालन करती नजर नहीं आ रही है, जिसकी भारत की पहल हकदार है। अमेरिकी आयात पर भारत में लागू टैरिफ पर ट्रम्प का भारत को लगातार कोसना राजनयिक शिष्टाचार के खिलाफ है। यह नीचा दिखाने वाला कृत्य है। कूटनीतिक दबाव बनाकर अमेरिका भारत से कई रियायतें चाहता है। सबसे खतरनाक कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बंद करने की मांग है। अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलना भारत के लिए आत्मघाती हो सकता है।

ट्रम्प की अपेक्षाएं असंतुलित और एकतरफा हैं। भारत को गांठ बांध लेना चाहिए कि ट्रम्प को खुश करना भारत के लिए जोखिम भरा है। यह अंतहीन है। कहना मुश्किल है कि ट्रम्प आगे क्या करेंगे? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रो. अमितेंदु पलित का कहना है कि ट्रम्प की आदत है कि एक बार आपने उनकी बात मान ली, तो जरूरी नहीं है कि यह आखिरी बात है। भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है।

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

आओ फागुन... आओ
कि तुम्हारे पलाश में
अबकी डूब मैं जाऊँ
कि मैं ही फाग हो जाऊँ
और तुम मुझे गाओ
कि गुलाल हो जाऊँ
और तुम फूँक दो ऐसे
कि मैं दिशाएँ बनूँ
और लाल हो जाऊँ
कि ढोल हो जाऊँ
और ताल तुम दे दो
कि मैं दरवेश हो जाऊँ
और नाच तुम हो लो
यूँ नहीं कि बस जैसे
तुम्हें देखता हूँ मैं
यूँ मिलूँ तुमसे
कि दूध भात हो जाऊँ
आओ फागुन ... आओ।।

– विवेक चतुर्वेदी

स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया आरएसएस भी वही सिखाता है

पॉडकास्ट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, तीन घंटे का दिया लंबा इंटरव्यू

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और

- कहा-पाकिस्तान को शपथ समारोह में बुलाया, लेकिन विश्वासघात हुआ

मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। उन्होंने कहा कि बचपन में संघ की सभाओं में जाना हमेशा अच्छा लगता था। मेरे मन में हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था, देश के काम आना। यही संघ ने मुझे सिखाया। आरएसएस इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संघ दुनिया में नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, 'संघ को समझना आसान काम नहीं है। इसके कामकाज को समझना होगा। यह अपने सदस्यों को जीवन का उद्देश्य देता है। यह सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया है, संघ भी यही सिखाता है। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नामक संगठन की शुरुआत की। उनके देश भर में करीब 25 हजार स्कूल चलते हैं। एक समय में 30 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ते हैं।' उन्होंने कहा कि वामपंथियों की ओर से प्रचारित श्रमिक आंदोलन दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ! का नारा लगाते हैं, जबकि संघ का श्रमिक संगठन मजदूरों, दुनिया को एक करो! का नारा लगाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचपन में कुछ ना कुछ करते रहना मेरा स्वभाव था। उन्होंने कहा, हमारे यहां एक व्यक्ति आते थे जो डफली जैसा कुछ रखते थे और देशभक्ति के गीत सुनाते थे। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। अलग-अलग जगह पर उनके कार्यक्रम होते थे। मैं पागल की तरह उन्हें सुनने चला जाता था। मैं रात-रात भर देशभक्ति के गाने सुनता था। इसमें मुझे मजा आता था। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा क्यों होता था, पता नहीं। ऐसे में संघ की शाखा लगती थी जहां खेल-कूद तो नहीं होता था। देशभक्ति गीत बजते थे जिसे सुनकर मन को बड़ा सुकून मिलता था। पीएम बोले जब भी हम शांति की बात करते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मैंने अपने शपथ में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। ताकि एक नया अध्याय शुरू कर सकूं, लेकिन शांति के हर प्रयास का बदला विश्वासघात मिला।

पाकिस्तान में लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर

- जम्मू-कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर करवाया था हमला

इस्लामाबाद (एजेंसी)। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कताल लश्कर का अहम सदस्य था और जम्मू-कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। पिछले साल 9 जून को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में भी कताल का हाथ था। इसमें 10 लोगों की जान गई थी। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि इस हमले में आतंकी हाफिज सईद भी मारा गया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि जब अबू कताल अपनी कार से झेलम इलाके से गुजर रहा था, तो बाइकसवारों ने कार पर ओपन फायर कर दिया।

राजगढ़ में सीएम यादव बोले-

किसानों को सोलर पंप देकर बिजली फ्री करेंगे

राजगढ़ (नप्र)। कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के दौरान योजनाओं की राशि बंद कर देंगे। लेकिन कोई योजना बंद नहीं होगी, पैसे भी बढ़ाएंगे। बहन-बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उससे परिवार को फायदा होता है। कांग्रेस के लोग सांप को ही पकड़ कर बैठे हैं। जो करेगा वो बढ़ेगा, यह जनता की आवाज है।

30 लाख किसान हैं, जिनके खेतों में बिजली के कनेक्शन हैं, हमारी सरकार एक-एक करके तीन साल के अंदर सबको सोलर पंप देकर बिजली फ्री करने वाली है। इसी साल 10 लाख बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। थोड़ी ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी तो सरकार उसे खरीदेगी। इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश के जरिए लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ जिले में लगने वाली हैं। जो भी बेहतर हो सकेगा वो सब हम करने के लिए तैयार हैं।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जनसभा में कहीं। उन्होंने शहर में पहुंचने पर सबसे पहले वीर शहीदों की स्मृति में बने शौर्य स्मारक का लोकार्पण किया।

5 साल में ढाई लाख नौकरियां देंगे

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हर व्यक्ति को दो रोटी मिलना चाहिए। हमारी तो संस्कृति ही जिओ और जीने दो वाली संस्कृति है। स्कूल शिक्षा विभाग में 19 हजार 362 नियुक्तियां करने वाले हैं। पुलिस विभाग में साढ़े हजार जवान हमने नियुक्त कर दिए, साढ़े 8 हजार की नई भर्ती निकलने वाली है।

राजगढ़ के नाराजगढ़ हो जाए पता नहीं चलता

उद्बोधन के दौरान सीएम यादव ने कहा कि राजगढ़ के नाराजगढ़ हो जाए पता नहीं चलता। जब यहां दाल-बाफले और दाल बाटी खाते हैं तो लगता है रात भी यहीं रुक जाओ। मन ही नहीं करता कहीं जाने का। राजगढ़ के लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजगढ़ में विकास हो रहा है। खेती के लिए यहां कांग्रेस ने कोई प्रबंधन नहीं किया, लेकिन आज यहां से ऐसी कोई नदी नहीं जो न बहती है। क्या पार्वती नदी आनंद आ रहा है, हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

नए जिला अस्पताल का उद्घाटन किया

जनसभा से पहले मुख्यमंत्री ने 200 बिस्तरों वाले नए जिला अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए जिला अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अब मरीजों को इलाज के लिए उज्जैन, भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

रंगों की फुहार... उदयपुर में बारूद की होली, रातभर चली तोप-बंदूकें

आपस में तलवारें टकराईं, युद्ध जैसा नजर आया होली का माहौल

उदयपुर (एजेंसी)। आधी रात को हाथों में तलवारें लिए लोग। आग उगलती तोपें और बारूद के धमाके, बंदूकों की गूंज। माहौल ऐसा, जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित मेनार गांव में शनिवार रात ऐसा ही नजारा था। उदयपुर में करीब 450 साल पहले मुगल चौकी ध्वस्त करने की खुशी में यहां मेनारिया समाज ने बारूद की होली खेली गई। इस दौरान तोपों से लगातार बारूद के धमाके किए गए। ढोल-दुंदुभि बजाए गए। तलवारों से गेर डांस किया गया। मशाल लेकर गांव के रास्तों की मोर्चाबंदी की गई। इसे देखने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दुबई तक से लोग मेनार गांव पहुंचे। उन्होंने कहा- इस परंपरा पर वैसा ही गर्व है, जैसा बॉर्डर पर युद्ध के समय होता है। होली के बाद दूज तिथि पर हर साल मेनार गांव में बारूद की होली खेली जाती है। गांव के दर्ज इतिहास के मुताबिक- मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के साम्राज्य के दौरान जगह-जगह मुगलों की छावनियां (सेना की टुकड़ियां) बनी हुई थीं।

परंपरा निभाई, जाजम बिछाकर की मेहमान नवाजी

शनिवार दोपहर ऐतिहासिक बारूद की होली की शुरुआत हुई। सबसे पहले गांव के ओंकारेश्वर मंदिर के चौक में शाही लाल जाजम बिछाई गई। गांव और आसपास के इलाकों से यहां पहुंचे मेनारिया ब्राह्मण समाज के पंचों, मौतवीरों (बुजुर्ग) का स्वागत किया गया। उनकी मेहमाननवाजी की गई। इसके बाद गांव के जैन समाज के लोगों ने अबीर-गुलाल बरसाना शुरू किया। सभी लोग आपस में गले मिले और होली की शुभकामनाएं दीं। इस बारूद की होली को देखने के लिए शनिवार शाम तक राजस्थान के कई शहरों के अलावा मध्यप्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र के मुंबई और दुबई तक से लोग यहां पहुंचे। रात तक उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर गाड़ियां पार्क की गईं। करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर लोग आयोजन स्थल तक पहुंचे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c

न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 17 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

हो जाएं सावधान! अबकी गर्मी बरपाएगी कहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत समेत देशभर में गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। इस बीच, ओडिशा में 16-18 मार्च के बीच हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना में 16-17 मार्च, छत्तीसगढ़ में 16, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में 18-20 मार्च के बीच हीटवेव का अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आंधी तूफान व भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 16 और 17 को तेज बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई। वहीं, असम, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल और माहे में भी बरसात हुई।

● देश के कई राज्यों के लिए हीटवेव की चेतावनी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अरुणाचल प्रदेश में 16 और 17 मार्च को तेज बारिश होगी। वहीं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में भी 16 और 17 मार्च को बारिश होने वाली है। वहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। वहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 16 मार्च को बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले चार से पांच दिनों में गर्मी बढ़ने वाली है और अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मध्य भारत में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। ओडिशा के बौध में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल 5 अप्रैल को ऐसी गर्मी थी।

हमारे दिलों में भारत के प्रति प्रेम हमें आपस में जोड़ता है

आईजोल (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अमित शाह फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान गृहमंत्री के स्वागत में एक 7 साल की बच्ची ने भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम् का गायन किया, जिसे सुनने के बाद अमित शाह ने एक गिटार

● बोले अमित शाह, मिजोरम में 7 साल की गायिका को दिया गिटार

तोहफे में देते हुए, उसकी तारीफ भी की। इस पूरे वाकये को बाद में उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर भी साझा किया। इससे इतर गृहमंत्री ने इस दौरान असम राइफल्स की जमीन को मिजोरम सरकार को हस्तांतरित करने के समारोह में भी भाग लिया और असम राइफल्स की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसके बारे में जानकारी देते हुए अमित शाह ने लिखा,भारत के प्रति प्रेम हम सभी को जोड़ता है। आज आइजोल में मिजोरम की वंडर किड एस्तेर लालदुहामी हनामते को वंदे मातरम गाते हुए सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। सात वर्षीय बच्ची का भारत माता के प्रति प्रेम उसके गीत में झलकता है, जिससे उसे सुनना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया। आपको बता दें कि मिजोरम की बाल गायिका हनामते का 2020 में मां तुझे सलाम गीत गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तब पहली बार देशभर का ध्यान उनकी तरफ गया था। इस गीत के वायरल होने के बाद पूरे देश से उन्हें जबरदस्त प्रशंसा मिली, इतना ही नहीं मिजोरम सरकार ने भी उन्हें कई पुरस्कार दिए और राज्यपाल ने भी उनकी विशेष प्रशंसा की थी। इसके अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम पर पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचे गृहमंत्री शाह ने असम राइफल्स की जमीन को मिजोरम सरकार को हस्तांतरित करने के एक कार्यक्रम में भी भाग लिया।

हटाओ औरंगजेब की कब्र, नहीं तो बाबरी स्टाइल में कारसेवा

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी बॉलीवुड फिल्म छावा रिलीज के बाद जहां सुर्खियों में तो वहीं दूसरी तरफ राज्य हिंदुवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने कहा कि औरंगजेब की कब्र हटाओ हटाने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर बाबरी स्टाइल में कारसेवा करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर बोले थे। उन्होंने कहा था कि हमें भी लगता है औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई संरक्षण मिला, कुछ चीजें कानूनी तौर पर करनी पड़ती है। यह भी सामने आया है कि विवाद के बाद इस कब्र पर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। इससे पहले राज्य में औरंगजेब को लेकर तब विवाद खड़ा हुआ था जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुंबई की

मानखुर्द शिवाजीनगर से विधायक अबु आजमी ने मुगल शासक की तारीफ की थी। अबु आजमी इस मामले में बेल पर हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानमंडल के पूरे बजट सत्र से सस्पेंड किया जा चुका है।

सिर पर गिलास, जमाल कुडू पर जमकर धमाल

● संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का गजब होली डांस ● सीओ अनुज चौधरी भी बलम पिचकारी पर जमकर नाचे

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस कप्तान का गजब होली डांस भई वाह देखकर चौंक जायेंगे आप सिर पर मिट्टी का गिलास और शानदार बैलेंस बनाकर गानें की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई। उनके इस अद्भुत होली डांस का जब रविवार को वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई उनके डांस को लेकर चर्चा करता सुना जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल बीते साल 24 नंवबर को हिंसा के बाद से चर्चा में आ गया है। लिहाजा संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा है। वहीं तेज तर्रार कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई ने हिंसा के बाद उपद्रवियों पर ऐसा कार्यवाही का चाबुक चलाया कि कुछ समय के लिए खराब हुए संभल के हालात संभलते देर ना लगी। इसके बाद अब होली पर्व और जुम्मे की नमाज एक साथ होने के चलते संभल पुलिस व प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी थी। ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लिहाजा संभल एसपी ने प्रशासन की

देखरेख में होली व जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे इन्तजामात किए कि चाह कर भी कोई भेद नहीं सकता था। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और सीसी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन की पहरेदारी थी। आईपीएस अनुकृति शर्मा ने भी महिला पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया। सीओ अनुज चौधरी को पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने बलम पिचकारी गाने पर डांस किया। सुबह डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण विश्नोई ओपन जिप्सी से ऑफिस पहुंचे। जिप्सी में रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना बज रहा था। जैसे ही डीएम-एसपी जिप्सी से उतरे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रंग और गुलाल लगाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से रंग बरसाए गए। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को दौड़ाकर रंग लगाया। फिर डीएम, सीओ और एसपी को पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठा लिया और जमकर थिरके। इस दौरान पुलिस लाइन में बने गड्डे में पानी भरा गया, जिसमें एसपी और पुलिसकर्मी कूद गए। उन्होंने एक-दूसरे पर पानी की बौछारें मारीं और हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाए।

उत्तरी मैसेडोनिया के नाइट क्लब में आग से तबाही

स्कॉप्जे (एजेंसी)। उत्तर मैसेडोनिया के कोचानी शहर के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने तबाही मचाई है। आग लगने की घटना से 51 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। मरने और घायल

● अग्निकांड में 51 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

होने वाले ज्यादातर युवा है, जो संगीत कॉन्सर्ट में आए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा रविवार रात ढ़ाई बजे हुआ है। स्थानीय पॉप ग्रुप के कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी से निकली चिंगारी से आग लगी, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। भारी भीड़ होने के चलते चीजें खराब हो गईं और बड़ी संख्या जनहानि हुई। हादसे पर उत्तर मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री ह्रीस्तिजान मिकोस्की ने दुख जताया है। उत्तर मैसेडोनिया के गृह मंत्री पांचे तोशकोवस्की ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की वजह आतिशबाजी है।

पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटे बलूच लड़ाके

बीएलए का दावा-90 सैनिक मारे, 5 दिन पहले ट्रेन हाईजैक किया था

इस्लामाबाद (एजेंसी)। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रविवार को पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमले का दावा किया है। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमला क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नोशकी के हाईवे के पास किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदायीन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया।

इसके बाद फतेह स्क्वॉड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था, वो पूरी तरह तबाह हो गया। घायलों को नोशकी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाकिस्तानी चैनल ट्रिब्यून पीके डॉट कॉम के मुताबिक, नेशनल हाईवे एनएच-40

पर हुए इस आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस नुष्की से तफ्तान जा रही थी, जब इसे निशाना बनाया गया। घायलों को तुरंत नुष्की अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन की हालत नाजुक बनी हुई है।

हाथरस में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बवाल

● आरोपी भी नाबालिग, गुस्साई भीड़ ने धार्मिक स्थल पर चलाए पत्थर

हाथरस (एजेंसी)। यूपी के हाथरस में सात साल की एक बच्ची के साथ रेप की बात सामने आने के बाद बवाल मच गया। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग है। गुस्साई भीड़ ने एक धर्मस्थल की ओर पत्थर चलाए तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह उनका गुस्सा शांत कराया। हंगामे और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह बात सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने एक धर्मस्थल की ओर पत्थर भी फेंके। सूचना पर हाथरस के एसपी, कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को इस गांव की सात साल की एक बच्ची दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी।

माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों ने बनाया अनोखा कीर्तिमान

● सोना-चांदी और नकद दान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जबरदस्त इजाफा

जम्मू (एजेंसी)। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का दान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने के बाद, मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। बीते पांच वर्षों में मंदिर को मिलने

वाला दान 171.90 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2020-21 में सिर्फ 63.85 करोड़ था। न केवल नकद चढ़ावा, बल्कि सोने और चांदी के दान में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी तक) में बढ़कर 171.90 करोड़ हो गया है। यह 2020-21 में केवल 63.85 करोड़ था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी एक आवेदन के जवाब में दी है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, सोने का चढ़ावा 2020-21 में 9.07 किलोग्राम था, जो 2024-25 (जनवरी तक) में बढ़कर 27.71 किलोग्राम हो गया है।

रूस ने कर दिया 'तेल' पर अब तगड़ा खेल

● क्रिप्टोकरेंसी से अमेरिकी बैन का निकाल लिया है तोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस ने अमेरिका के बैन का तोड़ निकाल लिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैन से बचने के लिए रूस तेल व्यापार में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। पिछली

गर्मियों में उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल करेंसी से पेमेंट की अनुमति देने वाला कानून भी पारित किया था। लेकिन तेल व्यापार में इसके इस्तेमाल की खबर पहले कभी नहीं आई थी। कुछ रूसी तेल कंपनियां चीनी युआन और भारतीय रुपये को रूसी रूबल में बदलने के लिए बिटकॉइन, ईथर और टीथर जैसी स्टेबलकॉइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि रूस के कुल तेल व्यापार में क्रिप्टो का इस्तेमाल अभी कम है, लेकिन यह बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पिछले साल रूस का तेल व्यापार 192 अरब डॉलर का था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी सूत्रों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की बात कही है। क्रिप्टोकरेंसी पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों वाले देशों जैसे ईरान और वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्थाएं चलाने में मदद कर रही हैं।

बंगाल में हिंसा रुक ही नहीं रही, सीएम योगी का वार

25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में सब शांत रहा

गोरखपुर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। जहां रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। जो अन्य तीनों स्तंभों को जोड़ता है और उन्हें सकारात्मक पहलू के बीच लाने में माध्यम बनता है। ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह सकें।

सीएम योगी ने कहा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं (पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए) जिनके यहां आए दिन हिंसा हो रही है और उनसे संभाला नहीं जा रहा। जबकि 25 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में तो जुम्मे की नमाज और होली एक

ही दिन मनाई गई और कुछ भी नहीं हुआ। इस बात पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब सब कुछ सही होने के बावजूद नकारात्मकता फैलाई जा रही है।

तो मैंने उनसे कहा कि यह दाल में तड़के के समान है। जिस तरह बिना तड़के के दाल अच्छी नहीं लगती इस तरह कुछ लोगों को बिना मिर्च मसाले के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दाल में जीरे का तड़का लगे तो वह भी काला हो जाता है।

सीएम योगी ने इस दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में लाउड स्पीकर की जरूरत आवश्यकता से अधिक बढ़ती जा रही है।

हालांकि यह जरूरी है, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि आयोजन स्थल पर उसकी ध्वनि का प्रसार इतना ज्यादा तेज ना हो ताकि बाहर के लोगों को उससे दिक्कत महसूस हो। चाहे वह किसी भी धर्म और समुदाय का आयोजन क्यों ना हो, इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा जाए और आने वाले वक्त में इसे लागू कर सख्ती से इसका पालन किया जाए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए। रविवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर क्लब में आयोजित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

कॉमरेड शाकिर अली खान को उनकी वामपंथी चेतना के साथ याद करें

भोपाल। अपने समय के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड शाकिर अली खान के स्मृति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में शाकिर सदन में 'कॉमरेड शाकिर अली खान की राजनीतिक चेतना का महत्व' विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रबुद्ध वक्ताओं ने कॉमरेड शाकिर अली खान के प्रेरक अवदान को उनकी वामपंथी राजनीतिक चेतना के साथ याद करना ही सार्थक श्रद्धांजलि निरूपित किया।वरिष्ठ साहित्यकार कॉमरेड इकबाल मसूद ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड डी डी शर्मा ने की । भाकपा नेता कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने मुख्य वक्तव्य दिया । इस अवसर पर भारतीय रेल के सेवा निवृत्त कर्मचारी अरविन्द कुमार सक्सेना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि शाकिर अली खान साहब एक आदर्श कॉमरेड थे। उन्होंने जीवन में घनघोर संघर्ष और कठोर अनुभवों से जीवन की पाठशाला में मार्क्सवाद की समझ और वामपंथी राजनीतिक चेतना को अर्जित किया था।वे अपने समूचे परिदृश्य के आदर्श और प्रेरक नेता थे। उनके अवदान को वामपंथी राजनीतिक चेतना से विमुख करके देखना निरर्थक और शाकिर साहब जैसी महान हस्ती की छवि के साथ अन्याय होगा। कॉमरेड शाकिर अली खान साहब को उनकी वामपंथी राजनीतिक चेतना के साथ याद करना ही सार्थक श्रद्धांजलि है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कॉमरेड इकबाल मसूद ने कहा कि शाकिर साहब अपनी वामपंथी राजनीतिक चेतना के साथ जिस तरह अपने परिदृश्य और अपनी ज़मीन से जुड़े थे, उससे हमें सीखना चाहिए। संगोष्ठी के अध्यक्ष वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड डी डी शर्मा ने कॉमरेड शाकिर अली खान साहब की प्रतिबद्धता, पक्षधरता और राजनीतिक चेतना के महत्व को रेखांकित किया। संगोष्ठी में एटक के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड शिवशंकर मौर्य, कॉमरेड बी एस बनाफर ,कॉमरेड एम एल सातपुते और कॉमरेड अरविन्द कुमार सक्सेना ने भी शाकिर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की।

एएसआई स्व. गौतम को दिया जाएगा शहीद का दर्जा : मुख्यमंत्री

- *परिवार को एक करोड़ रुपए की सहायता और पात्र उत्तराधिकारी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा*

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिला मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में हुई दुर्घटना में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले एएसआई (25वीं बटालियन) श्री रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्व. गौतम के आश्रितों को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद रामचरण गौतम के पात्र उत्तराधिकारी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। यह उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा, आस्था और राज्य सरकार की परंपरा व कर्तव्य का प्रकटीकरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद रामचरण गौतम की कर्तव्य परायणता और उनका बलिदान चिर-स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए यथा योग्य व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

शराब पिलाने से इनकार पर युवक को पीटा

- **चार बदमाशों ने सिर पर मारी बीयर की बोतल, हालत गंभीर**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहपुरा इलाके में तीन बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने साथ शराब नहीं पीने के चलते युवक के सिर पर बीयर की बोतल मार दी। आरोपियों ने युवक को धमकाते हुए जमकर मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। युवक के सिर, हाथ और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शराब के लिए बनाया दबाव, फिर हमला: पीड़ित मनीष यादव (24) शाहपुर इलाके का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि 15 मार्च की शाम 4:30 बजे वह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में आकाश सिंह उर्फ भूरा, धीरेंद्र पटेल, रक्का और सूरज लाला ने उसे रोक लिया। सभी को वह पहले से जानता था। आरोपियों ने मनीष से शराब पिलाने के लिए कहा। जब उसने मना किया, तो चारों आग-बबूला हो गए। देखते ही देखते आकाश ने पास रखी बीयर की बोतल उठाई और मनीष के सिर पर दे मारी। बोतल टूटने से उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन हमलावरों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसके हाथ और पेट पर भी वार किए।

जनसामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रतिबद्ध है सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने भिंड स्थित अतिशय क्षेत्र बरासों में सुमेरु पर्वत निर्माण का किया शिलान्यास

- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में भोपाल से वर्चुअली हुए शामिल**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जनसामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कार्य कर रही है। विश्व में भारत की पहचान हमारे आध्यात्मिक विचारों तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित करने से निर्मित हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भिंड में स्थित अतिशय क्षेत्र बरासों में सुमेरु पर्वत निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को राजकीय विमानतल भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बरासों में 414 फीट ऊंचे सुमेरू पर्वत का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की ख्याति सबको जीने का हक देने वाले देश के रूप में रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में, जीवन के सभी क्षेत्रों में गौरव अर्जित कर रहा है। भारतीय ज्ञान परम्परा के आध्यात्मिक तेज के साथ-साथ विश्व में देश की साख और धाक बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। प्रदेश में दूध उत्पादन के साथ-साथ दूध के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन पर गौ-पालकों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं को दिए जा रहे अनुदान को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान भारत में तीसरा है, हमारा प्रयास प्रदेश को देश में नंबर वन बनाने का है। दूध पर 5 रूपए प्रति लीटर बोनस की व्यवस्था की जाएगी, इससे कृषकों की आय बढ़ेगी और समाज सम्पन्न होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरासों में बनाए जाने वाले स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित अन्य जनकल्याण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञानार्जन के क्षेत्र में भी विशेष नवाचार किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरासों के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। भिंड के बरासों में आयोजित कार्यक्रम को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, दिगम्बर संत आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज, परम पूज्य रामदास जी महाराज ने भी संबोधित किया। मंत्री श्री शुक्ला ने यहां बनने वाली गौ-शाला, विद्यालय और अस्पताल आदि के लिए दान देने वाले दानदाताओं तथा अन्य सहयोगियों का आभार माना। आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज ने कहा कि सात्विक, सदाचारी, शाकाहारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में गतिविधियों का विस्तार हुआ है।

युवक की गला रेतकर हत्या

पुलिस बोली- किन्नरों ने चाकू से वार किए, थाने से 200 मीटर दूर किया हमला

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गला रेतकर सीने पर चाकू से वार किए गए। पुलिस के मुताबिक, हत्या का आरोप किन्नरों पर है। हमले में दो किन्नर भी घायल हुए हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद क्या था? वारदात रविवार सुबह करीब 8 बजे बैंड मास्टर चौराहे की है। मृतक की पहचान आदिल के रूप में हुई है। उसके भाई ने बताया- सुबह लगभग 6 बजे कुछ दोस्त आदिल के घर पहुंचे। उसे अपने साथ ले गए। वे लोग कार से आए थे, लेकिन उसे घर के पास खड़ी कर बाइक से निकल गए। करीब 8.30 बजे हमें सूचना मिली कि गंभीर रूप से घायल आदिल सड़क पर पड़ा है। हम मौके पर पहुंचे और आदिल को हमीदिया अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से तलैया थाना महज 200 मीटर दूर है। आदिल की शादी 22 फरवरी को हुई थी। करीब डेढ़ साल पहले आदिल के भाई आमिर बरखेड़ी का मर्डर जहांगीराबाद इलाके में हुआ था।

प्रत्यक्षदर्शी बोला- किन्नरों ने हमला किया

प्रत्यक्षदर्शी मुन्नवर अली ने कहा, मैंने देखा कि चार किन्नर आदिल को लात-घूंसे मार रहे थे। हमने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। झगड़े में एक किन्नर को भी चोट लगी है। एक अन्य के हाथ में जख्म हुआ है। थाना प्रभारी सीएस राठौर ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किन्नरों ने चाकू मारकर आदिल को घायल किया था। मामले की विवेचना जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदेहियों को भी चोट आई है, वे इलाज के लिए गए हैं। उन्हें पुलिस जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।

मेल ट्रेन मैनेजर ने घर जाकर लौटाई खोई हुई पायल

पूर्व मंत्री ने जताया रेलवे मैनेजर का आभार, रेल प्रशासन ने की सराहना

भोपाल (नप्र)। पूर्व मंत्री प्रभू सिंह ठाकुर का परिवार केरला एक्सप्रेस के वी-5 कोच में सीट संख्या 49-50 पर मथुरा से बीना तक यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान परिवार की एक महिला सदस्य की चांदी की पायल सीट के नीचे गिर गई, जिसकी जानकारी उन्हें तुरंत नहीं हुई। जब मेल ट्रेन मैनेजर पीयूष कुमार सिंह को यह पायल मिली, तो उन्होंने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए सहयात्रियों और टिकट निरीक्षक से संपर्क किया। यात्री का पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने पता लगाया कि यह पायल पूर्व मंत्री प्रभू सिंह ठाकुर के परिवार की है। पीयूष कुमार सिंह ने न केवल पायल सुरक्षित रखी, बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वयं पूर्व मंत्री के निवास पर जाकर उनके परिवार को पायल वापस की। इस ईमानदारी और जिम्मेदारी से प्रभावित होकर ठाकुर ने पीयूष कुमार सिंह की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया। साथ ही, उन्होंने रेलवे प्रशासन को भी पत्र लिखकर पीयूष कुमार सिंह के कार्य की प्रशंसा की। बता दें कि यह घटना महीने भर पहले की है, 13 मार्च को जब प्रभू सिंह ठाकुर को पता चली तो उन्होंने तुरंत रेलवे मैनेजर को बुलाकर प्रशंसा पत्र दिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने कहा कि पीयूष कुमार सिंह का यह कार्य रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। उनके इस प्रयास से न केवल रेलवे प्रशासन का मान बढ़ा है, बल्कि यात्रियों के बीच रेलवे के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। भोपाल मंडल पीयूष कुमार सिंह के ऐसे प्रेरणादायक कार्य पर गर्व करता है। रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी और समर्पण से ऐसी घटनाएं न केवल रेलवे की छवि को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास भी पैदा करती हैं। पीयूष कुमार सिंह का यह कदम निस्संदेह एक मिसाल बन गया है।

मऊगंज में शहीद एएसआई पंचतत्व में विलीन

आदिवासी परिवार ने की थी हत्या, हमले में टीआई समेत 13 घायल

मऊगंज (नप्र)। मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में आदिवासी परिवार के हमले में जान गंवाने वाले एएसआई रामचरण गौतम पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी।इससे पहले रविवार दोपहर को एएसआई की पार्थिव देह गृह ग्राम सतना पहुंची। शव को देख वहां का माहौल गमगीन हो गया। एएसआई को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल, शाहपुरा के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने कल यानी शनिवार को एक युवक को बंधक बना लिया था। उसे छुड़ाने पहुंचे टीआई संदीप भारती और पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। तहसीलदार के हाथ-पैर तोड़ दिए थे। हमले में टीआई समेत 13 पुलिसकर्मी घायल हैं। इनमें 4 रीवा के संजय गांधी मेडिकल अस्पताल और बाकी मऊगंज के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। आदिवासी परिवार ने बंधक बनाए युवक की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद गांव में धारा 163 (आपातकालीन स्थिति में) लगाई गई है। यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है। रविवार सुबह प्रभारी मंत्री लखन पटेल गांव पहुंचे। रामचरण के भाई का कहना है कि पुलिस हालात को समझ नहीं सकी, इसलिए बड़ी घटना हो गई। रामचरण परिवार का इकलौता सहारा थे। वे 6 महीने बाद रिटायर होने वाले थे।

परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी: सीएम यादव ने मऊगंज में शहीद रामचरण गौतम के परिवार को एक करोड़ रुपए की सहयोग राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

परिवार में इकलौते कमाने वाले थे रामचरण: एएसआई रामचरण गौतम का शव सतना जिले के पवैया गांव लाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गौतम अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बेटे हैं। उनकी मौत की खबर से गांव में मातम है। गौतम के बड़े बेटे सुनील और परिजन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

भाई बोला- पुलिस स्थिति को समझ नहीं सकी

एएसआई के बड़े भाई रामजी गौतम का कहना है कि पुलिस स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाई, इसलिए बड़ी घटना हो गई। रामचरण गौतम 1984 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वे वर्तमान में रीवा जिले के शाहपुर में पदस्थ थे। हिंसा के दौरान उनकी ड्यूटी मऊगंज में लगी थी, जहां उपद्रवियों के हमले में जान चली गई।

हमीदिया अस्पताल प्रबंधन करेगा सीटी स्कैन और एमआरआई

6 करोड़ की सिटी स्कैन हो रही इन्स्टॉल, 7 दिन में आएगी 12 करोड़ की एमआरआई

भोपाल (नप्र)। नेशनल मेडिकल काउंसिल के नए नियमों के तहत अब मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई जांच का संचालन अस्पताल प्रबंधन को ही करना होगा। इसी के तहत गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमीदिया अस्पताल में भी यह सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है।

अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्लॉक वन में 6 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, जबकि 12 करोड़ की एमआरआई मशीन अगले सात दिनों में आ जाएगी।

वर्तमान में यह दोनों जांच की सुविधा प्राइवेट पार्टनर शिप मोड पर पुराने भवन में संचालित की जा रही हैं। जिसके कारण लोगों को जांच के लिए 700 मीटर तेज धूप में चलकर, स्ट्रेचर से या व्हील चेयर से जाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अप्रैल माह से इन दोनों जांचों का संचालन पूरी तरह से अस्पताल के प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

मरीजों को होगी सहूलियत, बचेगा अतिरिक्त सफर: अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी विभाग के पीछे ही इन दोनों मशीनों को स्थापित कर रहा है, ताकि इमरजेंसी में आने वाले ज्यादा से ज्यादा मरीजों की तुरंत जांच हो सके। वर्तमान में यह सुविधाएं प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पुराने भवन में संचालित की जा रही हैं, जिससे मरीजों को 700 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गर्मी में तेज धूप में चलकर जाना, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर से मरीजों को लाना-ले जाना मुश्किल भरा होता है। अब नई व्यवस्था से यह समस्या खत्म हो जाएगी।

किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिली: हमीदिया अस्पताल में अब तक कुल 7 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। हालांकि, बीते कुछ समय से आठवें ट्रांसप्लांट की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह रुका हुआ था। अब अस्पताल प्रबंधन ने पुष्टि की है कि किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन का रिन्युअल हो चुका है और जल्द ही अगला ट्रांसप्लांट किया जाएगा।

रातापानी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को दिखा बाघ

मुख्य सड़क के पास आया टाइगर, टूरिस्ट्स ने कैमरे में कैद किया दृश्य

रायसेन (नप्र)। रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में रविवार को पर्यटकों को एक बाघ दिखाई दिया। मुख्य सड़क से कुछ ही दूरी पर एक बाघ को घूमते हुए देखा गया। पर्यटकों ने इस अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पर्यटकों के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। बाघ को इतनी नजदीकी से देखने का अवसर मिलने पर सैलानी बेहद उत्साहित थे। रिजर्व में आए दिन सड़क किनारे बाघों की चहल-कदमी देखी जाती है।

90 से ज्यादा बाघों का निवास: बता दें कि रातापानी टाइगर रिजर्व में 90 से अधिक बाघों का निवास है। चिकलोद और आसपास के क्षेत्रों में बाघों की उपस्थिति आम बात है। हाल ही में बाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सड़क किनारे एक बाघ को देखा गया था।

भोपाल में नई गाइडलाइन का फिर विरोध

क्रेडाई ने कहा-20 साल से बिना लैंड यूज़ बदले हर साल कीमतों में बदलाव

सांसद बोले-जनप्रतिनिधियों की बैठक हो

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल की 1283 लोकेशन पर एवरेज 18 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 19 मार्च की शाम तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे और 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे पहले विरोध भी शुरू हो गया है। क्रेडाई सदस्यों का कहना है कि बिना मास्टर प्लान के लैंड यूज में बदलाव हो रहा है। वहीं, सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो।

सांसद शर्मा नवंबर-24 में भी साल की दूसरी (संशोधित) गाइडलाइन का विरोध कर चुके हैं। तब कई लोकेशन ऐसी थी, जहां 200 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित थी। इस पर वे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से भी मिले थे। इसके बाद भोपाल की गाइडलाइन होल्ड कर दी गई थी। अब फिर से नई गाइडलाइन प्रस्तावित की गई है।

जिसका विरोध भी होने लगा है। सांसद शर्मा ने कहा कि वाकई में कई लोकेशन के जरूरत के हिसाब से रेट बढ़ाने के प्रस्ताव है। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिले और सरकार को भी राजस्व का नुकसान न हो। इसे लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, निगम अध्यक्ष, जिपं अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक होना चाहिए। इसमें चर्चा के बाद ही गाइडलाइन लागू हो।

3 साल के लिए स्टेबल हो गाइडलाइन-मीक

क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि, भोपाल में प्रॉपर्टी के लैंड यूज पिछले 20 साल से यथावत रखे गए हैं। लेकिन गाइडलाइन दर और संपत्ति के मूल्यांकन में हर साल बदलाव हो रहा है। प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत जानने की कोई वैज्ञानिक विधि निर्धारित नहीं है। गाइडलाइन दरों में बदलाव के उल्लेखित सिद्धांतों में कई बिंदू सिर्फ अनुमान पर आधारित हैं। अनियोजित राजधानी में प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोषणा से जमीनों की कीमतों में अवांछनीय बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने बताया, पिछले एक दशक में इंदौर के मुकाबले भोपाल में सर्किल रेट में कई गुना वृद्धि पहले ही हो चुकी है। जिससे संपत्ति बाजार अस्थिर हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भोपाल में निवेश में कमी आई है और संपत्तियों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सर्किल रेट बढ़ाने से प्रापर्टी टैक्स में सीधी वृद्धि होती है। जिससे आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार गाइडलाइन रेट प्री-कोविड ईयर के स्तर पर लाए। यह कदम जनहित में होगा। तीन वर्ष के स्टेबल लॉक-इन पीरियड की मांग है। नई प्रस्तावित गाइडलाइन को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि, अब तक पूरी गाइडलाइन अपलोड ही नहीं की गई है।

इस बार इतनी प्रस्तावित की गई गाइडलाइन

इस बार शहर की 1283 लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। औसत 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, जो तीन साल में सबसे ज्यादा है। करीब 100 लोकेशन पर रेट दोगुने या उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग आपत्ति और सुझाव देने के लिए 19 मार्च की शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय, वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय परी बाजार और आईएसबीटी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

संपादकीय

कर्नाटक - कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण

कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा राज्य में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण शुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है और मुस्लिम वोट बैंक बचाने की कोशिश है। जाहिर है कि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने धर्म के आधार पर दिए जाने वाले इस आरक्षण को मुसलमानों का तुष्टीकरण बताकर उसका खुलकर विरोध कर रही है। यह मामला कोर्ट में शायद ही टिके। बावजूद इसके राज्य सरकार ने यह फैसला किया है तो इसके पीछे राजनीतिक मजबूरियां ज्यादा हैं बनिस्बत मुसलमानों का आर्थिक सामाजिक बेहतरी के। सिद्धारमैया कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव 'कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योमेंट एक्ट' के तहत मुसलमानों को पीडब्लूडी के सरकारी टेंडरों में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा इस साल के राज्य बजट प्रस्तुति के दौरान की थी। सरकार ने न सिर्फ ठेकों में आरक्षण बल्कि मुसलमानों की और भी कल्याण योजनाओं का ऐलान किया गया था। जिसमें मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए देना शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक में मुस्लिम बच्चों को फीस में 50 फीसदी की छूट पहले ही हासिल है। जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया सरकार का यह फैसला कोर्ट में टिकना कठिन है। क्योंकि यह असंवैधानिक है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार को इस बात का अख्तियार है कि वह रिजर्वेशन दे सकता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आदि में मुस्लिम को ओबीसी कैटिगरी में राज्य सरकार ने रखा है। कर्नाटक के मामले में नया सिर्फ यह है कि यहां पीडब्लूडी की टेंडर प्रक्रिया में रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 15 व 16 में रिजर्वेशन दिए जाने का प्रावधान है। एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में दाखिले के लिए आर्टिकल 15 के तहत प्रावधान है और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 16 में है। जबकि कर्नाटक सरकार ने यह आरक्षण टेंडर में दिया है और वह भी धर्म के आधार पर। लिहाजा इसकी संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह है। ध्यान रहे कि पिछली कर्नाटक सरकार (बीजेपी सरकार) ने अप्रैल 2024 में मुस्लिम ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कर्नाटक के मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से कहा गया था कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ओबीसी का चार फीसदी रिजर्वेशन जो खत्म किया है, उसके लिए कोई उनके पास कोई स्टडी नहीं है। वहीं 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर नौकरी में रिजर्वेशन न देने का जो फैसला किया गया है वह सोच विचार कर किया गया क्योंकि यह रिजर्वेशन असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 के खिलाफ है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसका फैसला दूरगामी होगा। दरअसल हमारे यहां धर्म के आधार पर आरक्षण के फैसले और उनका विरोध राजनीतिक गुणा भाग के आधार पर तय होता है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 9.5 प्रतिशत है। ज्यादातर मुसलमान उत्तर पश्चिम कर्नाटक में रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसका यह वोट बैंक एकजुट रहे। इस मामले में भाजपा का रवैया दोहरा है। वह कर्नाटक में तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण का विरोध करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में, जहां वह चंद्रबाबू नायडू की सरकार में सहभागी है, राज्य में मुसलमानों को धर्म के आधार पर 4 फीसदी आरक्षण का विरोध नहीं करती।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

भारतीय भाषाओं के सम्मान में है भाषा विवाद का हल

23 जनवरी 1958 को डॉ. राम मनोहर लोहिया ने श्री रामास्वामी नायकर से जेल में जाकर मुलाकात की थी। उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में डाला था। बातचीत में नायकर ने कहा था, मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं जानता तब लोहिया जी ने कहा था आप तमिल में बोले मैं हिंदी में। मेरे मित्र गोडे मुराहारी दुभाषिये का काम करेंगे तब श्री नायकर ने कहा था बहुत अच्छा-बहुत अच्छा और उनकी बात दुभाषिए के माध्यम से, तमिल व हिन्दी में ही हुई।

नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रावधान है कि जो प्रदेश इसे स्वीकार करेंगें, उन्हें भारत सरकार विशेष अनुदान देगी। चूंकि तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया, अतः भारत सरकार ने उसको दी जाने वाली अनुदान राशि रोक दी है। इस कार्रवाई से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन बहुत शुब्ध हैं। उन्होंने फिर से भाषा-राजनीति का दौर शुरु किया है। उन्होंने कहा है- 'हम एक और भाषा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। हम हिन्दी साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं करेंगें।'

उनके इस बयान के बाद तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आन्दोलन सड़कों पर शुरु हो गया है। रेलवे स्टेशनों के रेल पट्ट जो तमिल-हिन्दी-अंग्रेजी तीन भाषाओं में लिखे जाते थे, उनमें से हिन्दी नाम को पोता जा रहा है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी हिन्दी नामों के सार्वजनिक स्थल के नामपट्टों व विज्ञापनों को पोता जा रहा है। यह आश्चर्यजनक भी है और दुखद भी। तमिल नेतृत्व हिन्दी के विरोध में लगातार भ्रम फैलाता है। पहले तो इसी प्रश्न पर विचार करें कि क्या हिन्दी के साम्राज्यवाद जैसी कोई स्थिति है? या हो सकती है? क्या हिन्दी के प्रयोग की बात करना हिन्दी को थोपना है? हिन्दी का इस्तेमाल एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और अगर बारीकी से विचार किया जाए तो तमिलनाडु की भी आवश्यकता है।

सबसे पहले मैं तमिलनाडु की आवश्यकता पर चर्चा करूँगा। द्रविड बनाम आर्य के टकराव की चर्चा आजादी के पहले और आजादी के बाद तमिलनाडु में हुई थी। इसको लेकर समूचे प्रदेश में आन्दोलन और आंतरिक टकराव रहा है, परन्तु एक अघोषित और अलिखित समरसता तथा सांस्कृतिक एकता भी नजर आती है तमिलनाडु में अच्छी खासी संख्या में लोग मारवाड़ से व्यापार करने पहुंचते रहे हैं। पिछले कई दशकों से वहां रहकर व्यापार कर रहे हैं। वे तमिल भी बोलते हैं, हिन्दी भी बोलते हैं और अपने घरो में मारवाड़ी बोली का प्रयोग भी करते हैं। आज तक कभी भी इन व्यापारियों और तमिलों के बीच किसी दंगे की चर्चा नहीं सुनने को मिली। क्या यह इस बात का संकेत नही है कि हिन्दी का साम्राज्यवाद या हिन्दी को थोपने का भय स्वतः थोपा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि तमिल नैतृत्व तमिल जनता पर हिन्दी का भय थोपता है और कभी-कभी उत्तर भारत के राजनेता भी ऐसी नासमझी कर उत्तर भारत में 'तमिल अलगावा' जैसे जुमले का प्रयोग कर तमिल अलगाव का भय फैलाते हैं। मेरी राय में ये दोनों ही भय चुनावी राजनीति के थोपे हुये भय हैं। जस्टिस पार्टी का विरोध तमिलनाडु में द्रविड बहुसंख्यकों के ऊपर ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध में था, उनका आन्दोलन भी आर्यन सभ्यता जिसे द्रविण ब्राह्मणी सभ्यता मानते थे उसके विरोध में था। रामास्वामी पेरियार के राजनैतिक जीवन की शुरुआत भी आजादी के पहले की गाँधी के कांग्रेस पार्टी से हुई थीं। उन्होंने कभी भी गाँधी के खिलाफनहीं बोला।

23 जनवरी 1958 को डॉ राम मनोहर लोहिया ने श्री रामास्वामी नायकर से जेल में जाकर मुलाकात की थी। उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में डाला था। बातचीत में नायकर ने कहा था ,मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं जानता तब लोहिया जी ने कहा था आप तमिल में बोले मैं हिंदी में। मेरे मित्र गोडे मुराहारी दुभाषिये का काम करेंगे तब श्री नायकर ने कहा था बहुत अच्छा-बहुत अच्छा और उनकी बात दुभाषिए के माध्यम से, तमिल व हिन्दी में ही हुई।

के. कामराज जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, वे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते थे। बल्कि थोड़ी बहुत हिन्दी और तामिल का प्रयोग करते थे। परन्तु उनका विरोध न कभी तमिलनाडु में हुआ न कभी उत्तर भारत में। इलाहाबाद (बनारस) मे प्रतिवर्ष हजारों लोग तमिलनाडु से जाते हैं, जिन्होंने हिन्दी नहीं पढ़ी है और उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता परन्तु उन्हें उत्तर भारत में कोई असुविधा नहीं होती।

शिव की मान्यता तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सर्वव्यापी है. तमिल या आर्य शिव सभी को स्वीकार है। मैंने अक्सर तमिलनाडु में यात्रा के दौरान देखा है कि बड़ी संख्या मे तमिल भाषी परिवार के परिवार जत्थों में आगरा, मथुरा और कभी-कभी झाँसी भी जाते हैं। उन्हें केवल तमिल आती है उन्हें अंग्रेजी-हिन्दी नहीं आती, परन्तु अपनी यात्रा के काम लायक हिन्दी शह समझ लेते हैं. और अपने काम लायक तमिल। सहयात्री जो तमिल भाषी नही होते वे भी समझ लेते हैं। अगर बाजार करने वाले लोगो ने उत्तर भारत से जाकर तमिलनाडु में तमिल सीखी तो क्या तमिल भाषी लोग उत्तर भारत में अपने काम के योग्य हिन्दी नहीं सीख सकते? दरअसल वे सीख सकते है और सीखना चाहते है परन्तु उनके ऊपर मानसिक भय थोपा जाता है। उन्हें काम चलाऊ हिन्दी भी सीखने से रोकने का काम राजनीति करती है।

केन्द्रीय सेवाओं या निजी कम्पनियों में काम करने वाले उत्तर भारतीय जो तमिलनाडु में पदस्थ होते हैं उन्हें वहाँ काम में और अधिक सुविधा होगी, अगर वे तमिल जानते होगें। इसलिये वे अपने काम लायक तमिल सीख लेते हैं। इसी प्रकार अगर उत्तर भारत में काम करने वाले तमिल भाषी हिन्दी सीख लेते हैं, तो काम चलाऊ ही सही उन्हें उत्तर भारत में काम करने में विशेष सुविधा होगी। वे सीख भी रहें हैं। दिल्ली, उ.प्र., बिहार, म.प्र. आदि में बहुत सारे ऐसे पदों पर तमिल भाषी पदस्थ हैं। जिन्होंने हिन्दी विधिवत नहीं पढ़ी, परन्तु सीख ली है. आम लोगो से संवाद वे ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। मैंने तो पहले ही यह सुझाव दिया है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के द्वारा चयनित अधिकारियों के लिये उनके परिवीक्षा काल के दौरान उनके कैडर वाले राज्य की भाषा सीखने के लिये एक दो माह का विशेष अभ्यास वर्ग शुरु हो जाये, तो काफी समस्या हल हो सकती है। ये हजारों अधिकारी, कर्मचारी जो गैर तमिल राज्यों से तमिलनाडु में जाएंगे और जो तमिल भाषी हिन्दी पट्टी या गैर तमिल राज्यों मे जाएंगे वे भाषायी संकीर्णता और गलतफहमी को दूर करेगें। तमिल और आर्यन राजनीति जो अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये भाषाओं को लड़ा रहीं है, वह भी असफल हो जायेगी। भाषा को लेकर टकराव केवल तमिल बनाम हिन्दी हो ऐसा नहीं है। भाषा विवाद कई राज्यों में हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कर्नाटक के बेलगांव में एक बस में एक कन्नड़ भाषी के साथ मराठी भाषीयों ने मारपीट की। मराठी भाषीयों ने उस कन्नड़ बुर्जुग से मराठी में बात करना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, तो मराठी भाषियों ने उसके साथ मारपीट की। यानि भाषाई आग्रह और भाषाई कट्टरता केवल तमिलनाडु में ही नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी है। हालाकि चर्चा ज्यादा तमिलनाडु की होती है। श्री स्टालिन के पदचिन्ह पर चलते हुये केरल के कुछ राजनेताओं ने भी हिन्दी विरोधी चर्चा शुरु की, हालाकि केरल में उसके लिये कोई ज्यादा संभावना नहीं है। केरल वासियो की आबादी का बड़ा हिस्सा समूचे देश में और देश के बाहर भी काम के लिये गया है। अतः उनमें भाषाई समझ और सम्मिलन की भावना ज्यादा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वर्तमान दस्तावेज में वहीं त्रिभाषा फार्मूला का प्रावधान है जो पिछले लगभग सात दशकों से चला आ रहा है।

एक व्यक्ति अपनी मातृ भाषा या राज्य भाषा को पढ़ेगा, फिर अंग्रेजी पढ़ेगा और कोई एक भारतीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा पढ़ेगा। इसमें हिन्दी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगर श्री स्टालिन हिन्दी नहीं पढ़ाना चाहते तो वे कोई और भारतीय भाषा पढ़ा सकते हैं। वे मलयाली, कन्नड़, उर्दू तेलगू आदि कोई भी भाषा जिसमें उन्हें भाषाई साम्राज्यवाद नजर न आये, उसे पढ़ा सकते हैं। श्री स्टालिन के पिता स्व. करुणानिधि भी लम्बे समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। श्री स्टालिन को तो अब राष्ट्रीय राजनीति में भी न केवल एक राज्य के सहभागी के तौर पर बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर सहभागी बनना चाहिये। पर अगर वे केवल तमिल भाषा की राजनीति करते रहेंगे तो उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व क्षमता अन्य लोगों को स्वीकार्य नहीं हो सकेगी। उन्हें अब अपना दायरा बढ़ाना चाहिये।

तमिल साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है। परन्तु उसका फैलाव तमिलनाडु के भाषाई राजनीती के चलते उत्तर भारत में नहीं हो पा रहा।

एक वैश्विक वैचारिक ज्ञान संम्पदा को भाषा राजनीति ने केवल तमिलनाडु तक सीमित कर दिया। क्या यह इन राजनेताओं का स्वतरू अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति अपराध नहीं है?

मुझे लगता है कि आने वाली तमिलनाडु की पीढ़ियाँ यह महसूस करेंगी कि उनके नेतृत्व ने उनकी बौद्धिक क्षमता को अपने छोटे स्वार्थ के लिये सीमित कर दिया गया था। तमिल कलाकार अभिनेता जिन्हें सारे देश में देखा जाना चाहिए वे एक प्रदेश की आबादी में राजनीति के द्वारा सिकोड़े जा रहे हैं। मैंने तमिलनाडु के दौरों में कई मित्रों के घरों में हिन्दी फिल्मों को देखते हुये देखा है। वे उन्हे पसन्द करते हैं। और उसे तमिल में अनुवाद के साथ देखते है। जो कला का आदान-प्रदान समूचे देश व दुनिया में होना चाहिये वह एक इलाके में सीमित कर दी गई है। स्टालिन साहब स्वतः अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ अन्याय कर रहें है, मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहूँगा-

1. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं से सी सेट 2 को समाप्त करें और अंग्रेजी के पेपर की अनिवार्यता समाप्त करें।
2. तमिलनाडु सरकार और दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सामूहिक विभर्श के लिये आमंत्रित करें। ताकि भाषा विवाद के हल का मार्ग प्रशस्त हो और कटुता की राजनीति का अन्त हो।
3. अगर समस्या के हल के लिए भारत सरकार हिन्दी-अंग्रेजी दोनों को ऐच्छिक कर दें, तो भी एक रास्ता खुलेगा।
4. केन्द्रीय सेवाओं में चयनित लोगों के लिये उनकी पद स्थापना वाले राज्य की भाषा को सीखना अनिवार्य हो तथा इसके लिये चयनित लोगों के लिये विशेष भाषा के कोर्स शुरु करायें।

अंत में मैं तमिल बुद्धिजीवियों, तमिल केन्द्रीय कर्मचारियों और तमिल मित्रों से अनुरोध करूंगा की वे आगे आकर हस्तक्षेप करें। और अपने राष्ट्रीयदायित्व का निर्वहन करें।

विश्व राजनीति

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आतंकियों की चपेट में पाकिस्तान

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रेल अपहरण के बाद तय हो गया हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही देश के आतंकवादी संगठनों की चपेट में आता जा रहा है। पाकिस्तान की यह दुर्गति 'बीज बोए बबूल के, आम कहां से होएं' कहावत को चरितार्थ करने वाली है। पाकिस्तान की यह दषा आतंकवादियों को पालने-पोसने का परिणाम है। ये संगठन जिस तेजी से पाक में हमलावर बने हुए हैं, उसके चलते ऊंट अब पहाड़ के नीचे आता जा रहा है। बलूचों के हमले के बाद तहरीक-ए-पाकिस्तान (टीटीपी) ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि पाक सेना एक कैंसर है, इसे नहीं छोड़ेगे। टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान-अफगानिस्तान के सीमाई क्षेत्र में जारी है। 2007 में जन्मा टीटीपी 13 आतंकी समूहों का एकीकृत संगठन है। 2014 में इसी ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके 126 छात्रों को मार डाला था। टीटीपी के अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान (आईएसके) भी वर्तमान में मजबूत हो गया है। ये तीनों संगठन परस्पर संगठित होकर पाक के लिए सिरदर्द बन गए है। इसी का नतीजा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाक इस साल दूसरा सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश बन चुका है।

बीएलए ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित बड़ा अलगाववादी संगठन है। बलूचिस्तान क्षेत्र के पाक के कब्जे के आने के बाद से ही आजादी के लिए संघर्षरत है। जबकि अंग्रेजों ने इसे स्वतंत्र देश मान लिया था। लेकिन पीओके के साथ पाक ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया था, तब बलूचिस्तान पाक के मानचित्र में शामिल नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने बलूचिस्तान को कुछ कबाइली क्षेत्रों और कुछ स्वतंत्र रियासतों में बांट दिया था। इस स्थिति में कबाइली सरदार अकबर बुग्ती ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। इस फैसले के साथ मकरान, खारान और लसबेला रियासतों ने तो पाक में विलय होने की सहमती दे दी, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत कलात ने स्वतंत्र सूबा के रूप में बने रहने का निर्णय लिया। नतीजतन 1948 में कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन शाही परिवार के प्रिंस करीम ने आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इससे निपटने के लिए 1948 में बलूचिस्तान में पाक ने पहला सैन्य अभियान चलाकर सशस्त्र खिलाफत को अपदस्थ किया। किंतु आगे भी बलूचिस्तान में विद्रोह फूटते रहे, जिसके फलस्वरूप 1970 में बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दे दिया गया। यहां निर्वाचित सरकार भी बनी। जिसे 1973 में बर्खास्त कर दिया गया। तभी से यह क्षेत्र स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। परंतु सैनिक तानाशाह जियाउल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ी हुई। इसके बाद से ही जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारें के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान में कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ हैं। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर भी हमला इसलिए बोला गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पाक सैनिक यात्रा करते हैं।

गिलगित और बलूचिस्तान पर पाक ने 17 मार्च 1947 को सेना के बूते अवैध कब्जा कर लिया था, तभी से यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाले लोगों पर दमन और अत्याचार आज तक जारी है। अब इस लड़ाई में टीटीपी और आईएसके भी पाक पर हमलावर के रूप में पेश आ रहे हैं। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा यहीं है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच है। यहां हिंदु, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं। क्योंकि ये मतांतरित हिंदू हैं। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगे की खबरें नहीं आती हैं। 1977 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक शांति रही। लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए।

इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बीएलए ही है। पीओके और बलूचिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में आता है।

इसे ही पीओके कहा जाता है। पाक के लिए यह पूरा क्षेत्र बहिष्कृत हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। लेकिन अब कई आतंकी संगठनों ने मिलकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

वह रंगदारी करवा कर झाड़ता है अपना रौब

कटाक्ष

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

होली के आने की आहट पर मॉर्निंग वाकिए होली के वाकिये सुनाने के लिए पूरा मॉर्निंग वॉक होली टॉक में व्यतीत करने लगे थे। मॉर्निंग वॉक में शामिल पंडित शिवनारायण जी बोले हर कोई अपने अपने हिस्से की होली खेलते है। होली को होली के रूप में मनाने के लिए वर्तमान में होली के मापदण्ड, पैमाने बदल गए हैं। वैसे भी बुरा मानो या न मानो होली, होली है। लेकिन वर्तमान में होली पर लोग

इसलिए बुरा नहीं मानते हैं कि सब अपने अपने हिस्से की होली खेलकर होली को, हम जोली बना लेते है।पंडित जी बोले अपने हिस्से की होली नेता जी मनाते हैं! वे हर रंग में उसी रंग के हो जाते है। नेताजी के पास यदि कोई गुस्से में लाल पीला पड़ता है तो नेताजी भी लाल पीले पड़े उसके पहले उनके रंगदारी करने वाले लाल पीले पड़कर उनके लाल पीले पड़ने वाले रूख को बदल देते हैं। जनता यदि नेताजी के पास किसी समस्या को लेकर जैसे रंग का चेहरा लेकर आते वे उसी तरह का चेहरा बना लेते है।

यहीं नहीं अफ़सरों को वसूली करने वाले के स्थान पर सूली पर चढ़ने से बचाने वाले सयाने व्यापारी को मुनाफा खोर की जगह वाजिब कमीशन खाने वाला कहें, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले सरकारी मास्टर जी को नि:शुल्क कार्यक्रम कर वाह-वाही लूटने वाले कहे, भाई साहब जब दूसरे द्वारा खुद की बीबी पर रंग लगाने पर चेहरे को लाल करे और पड़ोसन भाभी जी पर रंग लगाने पर मुस्कान का रंग बिखेर दे तो मानो वे होली को अपने अपने हिसाब की होली मनाने के लिए सहमत है। होली पर अश्लील गीतों,छल्लो की बौछार कर किसी की भी इज्जत उछाल कर अपने हिस्से की होली मनाते हैं। होली पर हंगामा करें और कपड़े फटने पर कपीश जैसे सेल्फी ले तो यह भी सेल्फी मास्टर की होली का ही हिस्सा है।

इस पर सुनील भैया बोले, जब बड़े-छोटे, अमीर-गरीब, अफसर-मातहत, नेता-चमचे, मालिक-मुनीम, बुजुर्ग-बच्चे, बॉस-मुलाजिम सब पड़ोस की मेम साब पर रंग लगाने की परंपरा से अपने अपने हिस्से की होली मनाने से नहीं चुकते हैं। सभी गर्व से कहते हैं कि हमने हमारे हिस्से की होली मना ली।

वे बोले, रंग की अपनी तासीर है, वह रंगदारी करवा कर अपना रौब झाड़ता है। रंग का त्योहार, फाग महोत्सव, गेर निकालने वाले गेर के लिए गैरों से चंदा लेने वाले छुटभैया से बड़े नेता बनने का रंग होली के हिस्से से ले लेते है।

जब अपनी-अपनी होली की बात चली तो बदरंग जी बोले, होली का रंग सरकारी और अ-सरकारी भाषा भी जानता है, रंग वाले लिफाफे से ज्यादा वैल्यू बेरंग लिफाफे की होती है। किसी अहम कार्य के लिए जाने के बाद जब काम नहीं होता है तो उसे बेरंग लौटना भी कहते है। हाथ का रंग भ्रष्टाचार को नापने का बैरोमीटर तो है ही, चोरी छिपे काम करते पकड़ा जाना भी, रंगे हाथ से ही पहचाना जाता है। रंग बरसाने से लेकर रंगदारी कर, गिरगिट की तरह रंग बदल कर हर कोई अपने अपने हिस्से की होली मना कर होली के रंग से रंग जमा लेता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

हज़ार मर्ज़ों की दवा खरीददारी की बीमारी

व्यंग्य

प्रमोद ताम्बट

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सपनों में आप खुद को झोला उठाए बाज़ार में घूमते दिखायी दें, बड़े-बड़े शो रूम मॉल्स की चकाचौंध आँखों के सामने पिक्चर सी घूमती रहें, फ़ूड जोन, खस्ता चाट-पकौड़ी की खुशबुओं से नथूने फड़कते रहें, कदम बार-बार बिस्तर पर ही आपो-आप बाज़ार की ओर चल पड़ने को आतुर हों और साथ-साथ हाथ में प्रचंड खुजली सी भी मचती रहे तो समझ लीजिए आपको खरीददारी की बीमारी ने जकड़ लिया है। इस स्थिति में आप जब तक बाज़ार जाकर चार-छः घंटों का क़त्ल कर के आठ दस झोले-झाँगड़े हाथों में लटकाएँ ओला-उबर से थके-हारे घर नहीं लौटोगे तब तक इन रोज़ परेशान करने वाले सपनों की वजह से आपको रात-रात भर नींद नहीं आएगी। यदि आप घोड़े बेचकर चैन से सोना चाहते हैं तो आपको समय-समय पर बाज़ार की तरफ दौड़ लगाना ही पड़ेगी चाहे आपकी जेब में पैसे हों या न हों।

यकीन मानिए इस चरम पूँजीवादी मारामारी के दौर में खरीददारी की यह संक्रामक बीमारी आम आदमी के लिए अपने-आप में ख़ुद एक बहुत बड़ी प्राणदायी दवा बन गई है। दुनिया में कुछ भी उठापटक चलती रहे, बाज़ार उन्वान पर हों या ध्वस्त होते रहें, अर्थव्यवस्था रेंग रही हो या उड़ रही हो, आपकी माली हालत खस्ता हो तब भी खरीददारी की यह बीमारी स्थाई भाव से अपनी जगह बनी रहती है और बाकायदा स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक का सा काम भी करती रहती है। इस दवा के सामने कोई ताकतवर से ताकतवर लाइफ़ सेविंग ड्रग भी टिक नहीं सकती। कभी तबियत नासाज़ रहे रात भर नींद न आए या उचटी-उचटी सी आती-जाती रहे, सुबह उठते से ही आँखों के आगे अंधियारा सा छाया रहता हो। रह रह कर घुमेरी आती हो। चाय-नाश्ते की भी इच्छा ना हो। नहाने धोने सजने संवरने, तैयार होकर मटकने का भी मन न हो, प्राण निकले पड़ रहें हों तो आप फौरन अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उठाकर बाज़ार की तरफ़ निकल जाइये, बस फिर देखिए कैसे आपके प्राण वापस लौट आते हैं। कहीं जम के मुँह की खानी पड़ी हो, कहीं पिट-पिटा कर आएँ हों, परीक्षा में फेल हो गए हों, प्रेमी-प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया हो, इंडिया क्रिकेट मैच हार गई हो, मूढ बेहद खराब हो, बस उठकर चल दीजिए बाज़ार की ओर। बाज़ार में अगर आपने डॉक्टर की फ़ीस, पैथालॉजिकल टेस्टों और दवाओं की कुल कीमत से एक चौथाई कम रकम भी यदि खर्च कर ली तो समझ लीजिए आपकी बीमारी चंद लम्हों में छूमंतर हो जाएगी। यकीन न हो तो आज़मा कर देख लीजिए।

बात दरअसल यह है कि वैश्विक व्यापार व्यवसाय लॉबी ने खरीददारी की इस बीमारी को एक महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में ईजाद किया है और उसे गीता-रामायण से भी ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया है क्योंकि उनका मानना है कि उपलब्ध दवाओं से हमेशा की तरह बस मर्ज़ ही बढ़ते रहें और मरीज़ दम तोड़ते रहें तो उनके व्यापार-धंधों का क्या होगा। एक दिन दुनिया का सम्पूर्ण बाज़ार ख़रीददार विहीन हो जाएगा। दुकानों शोरूमों पर ताले लग जाएँगे। कॉर्पोरेट दफ्तर और बिज़नेस हब सूने हो जाएँगे। तिजोरियाँ भूखे पेट पड़ी रहने का मजबूर हो जाएँगी। सरकारों के पास भी करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने बहुत शोध-अनुसंधानों के पश्चात यह थेरेपी ईजाद की है और अब इसका उपयोग घर-घर में किया जाकर स्वास्थ्य लाभ लिया जाने लगा है।

मगर इधर चिकित्सा विज्ञान की दवा-गोली इंजेक्शन ब्राँच ने इस बात पर गंभीर आपत्ति ली है और हड़ताल इत्यादि करने की धमकी देकर विरोध दर्ज करा रखा है क्योंकि उनके मुताबिक अगर ख़रीददारी से ही मरीज़ ठीक होते रहे तो उनके दवा-गोली निर्माण के धंधे पर संकट आ सकता है। अस्पतालों, दवा-दारू की फैक्ट्रियों दुकानों, पैथोलॉजी सेंटरों, आधुनिक टेस्ट प्रणालियों के भट्टे बैठ सकते हैं।

आम पब्लिक को भी यदि अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा-दारू और खरीददारी में से कोई एक सुविधा चुनने के लिए कहा जाए तो वह भी शर्तिया खरीददारी को ही चुनेगी, क्योंकि पैसे तो आखि़र दोनों प्रकार की बीमारियों में खर्च होते हैं चाहे वह खरीददारी की बीमारी हो अथवा शारीरिक बीमारी। जिस बीमारी से बांछें खिल-खिल उठती हों वह बीमारी है असल बीमारी। खरीददारी की बीमारी दुनिया की एक मात्र ऐसी बीमारी है जो खुद तो खतरनाक बीमारी है मगर हज़ार मर्ज़ों दवा भी है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

लंबे लिव इन रिलेशन के बाद दुष्कर्म का आरोप गलत

अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल तक व्यक्ति की मांगों के आगे बिना किसी विरोध के इस आधार पर झुकती रही कि व्यक्ति शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। लंबी अवधि से साथ में रहने के कारण शिकायतकर्ता का दावा कमजोर हुआ। न्यायालय ने कहा कि सोलह साल तक दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे। यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी छल-कपट का तत्व नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में यह फैसला सुनाया कि महिला और पुरूष अगर लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कोई महिला पुरूष पर शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बैंक मैनेजर और लेक्चरर से जुड़े मामले में की। महिला की याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यह निर्धारित करना मुश्किल होता है, कि यौन संबंधों के पीछे की वजह सिर्फ शादी का वादा था या नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने महिला लेक्चरर की याचिका खारिज कर दी। महिला ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 साल तक यौन संबंधों में रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों साथ अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी एक-दूसरे से मिलते रहते थे। न्यायालय ने मामले को लिव-इन रिलेशनशिप करार दिया। खंडपीठ ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल तक व्यक्ति की मांगों के आगे बिना किसी विरोध के इस आधार पर झुकती रही कि व्यक्ति शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। लंबी अवधि से साथ में रहने के कारण शिकायतकर्ता का दावा कमजोर हुआ। न्यायालय ने कहा कि सोलह साल तक दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे। यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी छल-कपट का तत्व नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि झूठा वादा किया गया था, लेकिन रिश्ते की लंबी अवधि ने शिकायतकर्ता के इस दावे को कमजोर कर दिया कि उसकी सहमति केवल शादी की उम्मीद पर आधारित थी।

याचिकाकर्ता लेक्चरर ने आरोप लगाया था कि सन 2006 में रात को उसके साथ आरोपी ने जबरन यौन संबंध बनाए। न्यायालय ने कहा कि इस बीच अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठता बढ़ती रही। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ित पुरूष ने कहा कि संबंध सहमति से थे और लेक्चरर वयस्क और शिक्षित महिला होने के नाते स्वेच्छा से उसके साथ संबंध में थी। लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद महिला अपने साथ पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। खास बात है कि दोनों एक दशक से ज्यादा समय तक साथ रहे थे। न्यायालय ने इसे रिश्तों में खटास आने का मामला करार दिया है। साथ ही अपीलकर्ता पुरुष को आपराधिक कार्यवाही से राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ऐसे हालात में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के वादे के आधार पर बनाए गए थे। महिला के आरोप थे कि वह आरोपी बैंक अधिकारी के साथ शादी के वादे के आधार पर सौलह सालों तक संबंध बनाती रही।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता करीब सोलह साल अपीलकर्ता की हर मांग पर झुकती रही हैं। इस बात पर बगैर विरोध जताए रहीं कि अपीलकर्ता शादी के झूठे वादे के आधार पर उनका यौन शोषण कर रहा था। सोलह साल तक लंबे समय दोनों के बीच शारीरिक संबंध बगैर रोक-टोक जारी रहे। यह तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि रिश्तों में कभी भी जबरदस्ती या धोखा देने की बात नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि कथित तौर पर शादी का वादा किया गया था, तो इतने समय तक उनका रिश्ते में रहना उनके दावों को कमजोर करता है।

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में इसी तरह का रवैया अपनाया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सहमति से व्यभिचार शुरू होने के बाद से बलात्कार नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सहमति से संबंध और धोखे की कमी का हवाला देते हुए शादी का झूठा वादा करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी शुरुआत से ही धोखे के किसी भी तत्व के बिना लंबे समय से सहमति से व्यभिचारी शारीरिक संबंध

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अर्थ के भीतर बलात्कार नहीं होगा। यह बलात्कार को एक महिला के साथ उसकी सहमति के खिलाफ यौन संबंध के रूप में परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद के एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। इस पर शादी का वादा करने के बहाने एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था। उच्च न्यायालय की टिप्पणी यह थी कि शादी का वादा अपने आप सहमति से यौन संबंध को बलात्कार नहीं बनाता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसा वादा शुरू से ही गलत था।

न्यायालय ने कहा कि विवाह के प्रत्येक वादे को सहमति से यौन संबंधों के मकसद से गलत धारणा के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि विवाह का ऐसा वादा आरोपी की तरफ से रिश्ते की शुरूआत से ही झूठा वादा था। जब तक यह आरोप नहीं लगाया जाता कि इस तरह के रिश्ते की शुरूआत से ही आरोपी की ओर से इस तरह का वादा करते समय धोखाधड़ी का कुछ तत्व था, इसे शादी के झूठे वादे के रूप में नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने दायर याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ मुरादाबाद की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता पर एक महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। मुरादाबाद के महिला थाने में दर्ज अपनी प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसके पति की मौत के बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस महिला ने दावा किया था कि इस व्यक्ति ने उसके साथ बार-बार शादी करने का वादा किया था। लेकिन, बाद में उसने वादा तोड़ दिया और दूसरी महिला से सगाई कर ली। उसने उस पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने उनकी अंतरंग संबंधों को दिखाने वाले एक वीडियो को जारी करने से रोकने के लिए पचास लाख रुपये की मांग की थी।

इन आरोपों के आधार पर सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 386 (जबरन वसूली) के तहत दायर 9 अगस्त, 2018 के आरोप पत्र का संज्ञान लिया। हालांकि, आरोपी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप पत्र और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने तथ्यों को देखने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता जो एक विधवा है और आरोपी ने लगभग 12-13 वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखे। यह संबंध तब भी थे जब शिकायतकर्ता का पति जीवित था। उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने याचिकाकर्ता पर अनुचित प्रभाव डाला, जो उससे बहुत छोटी थी और दिवंगत पति के व्यवसाय में एक कर्मचारी था। नईम अहमद बनाम हरियाणा राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने दोहराया कि शादी के वादे के हर उल्लंघन को झूठे वादे के रूप में मानना और किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमा चलाना अनुचित होगा।

चोरी का साहित्य

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

प्रसिद्धि की बैसाखी बनता साहित्य में चौर्यकर्म

साहित्यिक चोरी साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गई है, जहाँ एक लेखक के विचारों, शब्दों या रचनाओं पर दूसरे लेखक द्वारा उचित स्वीकृति के बिना दावा किया जाता है। यह कृत्य न केवल साहित्यिक नैतिकता का उल्लंघन करता है बल्कि सच्चे लेखक की मौलिकता और रचनात्मकता को भी कमज़ोर करता है। कॉपी-पेस्ट करने का मुद्दा हिंदी साहित्य में तेज़ी से प्रचलित हो रहा है, खासकर इस डिजिटल युग में, जहाँ लेख, कविताएँ और कहानियाँ ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। साहित्यिक चोरी में किसी और के साहित्य को बिना श्रेय दिए लेना या उसमें मामूली बदलाव करके उसे अपना बताकर पेश करना शामिल है। यह व्यवहार मूल लेखकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और रचनात्मकता और मौलिकता को दबाता है। कुछ व्यक्ति इस हद तक चले जाते हैं कि वे दूसरों के साहित्य को अपना बता देते हैं। साहित्यिक चोरी के एक रूप में कहानी के पात्रों को बदलना और उसे मूल रचना के रूप में विपणन करना शामिल है। इस कुकृत्य में ऐसे लोग भी हैं जो स्थापित लेखकों की प्रसिद्ध कृतियों को अपनी कृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तथा अक्सर साहित्यिक क्षेत्र में मान्यता और प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं।

साहित्यिक चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे लेखक के शब्दों को बिना अनुमति या उचित श्रेय दिए अपने शब्दों के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ कोई लेखक बिना उचित उद्धरण के अपने पहले से प्रकाशित साहित्यिक काम का पुन: उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति मूल विचारों और संरचना को बरकरार रखते हुए किसी दूसरे की सामग्री में मामूली बदलाव करता है, तो उसे भी साहित्यिक चोरी माना जाता है। यह समस्या विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रचलित है, और दुर्भाग्य से, यह आज भी जारी है। साहित्यिक चोरी के कई रूप हैं, और यहाँ तक कि दोहराव को भी रचनात्मक चोरी के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई हिंदी लेखक होली या दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान विभिन्न प्रकाशनों में अपनी रचनाएँ पुन: प्रकाशित करते हैं। एक मजबूत समीक्षा संस्कृति की कमी ने साहित्यिक चोरी को साहित्य का एक परेशान करने वाला पहलू बना दिया है। आजकल, कोई भी किसी रचना को उसे बिना किसी जाँच के प्रकाशित करवा सकता है, जिससे ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ मूल लेखक ठगे रह जाते हैं। 'निजी' पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ लेना और उन्हें अपने नाम से प्रकाशित करना आम बात हो गई है। इस व्यवहार को खत्म करने के लिए केवल आलोचना ही अपर्याप्त लगती है। साहित्यिक चोरी सिर्फ़ नए लेखकों या प्रसिद्धि चाहने वालों की ही बैसाखी नहीं है; यहाँ तक कि स्थापित हिंदी लेखक भी दूसरों की रचनाओं में थोड़ा-बहुत बदलाव करके उन्हें अपना बता देते हैं। साहित्यिक चर्चाओं में साहित्यिक चोरी के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें कुछ लेखकों पर प्रसिद्ध पुस्तकों के अंशों को अपनी रचनाओं में शामिल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे अंतत: उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।

किसी अन्य लेखक के काम या विचारों का उपयोग करते समय, उचित श्रेय देना आवश्यक है। अपने स्वयं के विचारों और शैली को व्यक्त करके मौलिक लेखन को अपनाएँ, यह सुनिश्चित करें कि हिंदी साहित्य में नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता पनपे। दूसरों के काम की अनजाने में नकल करने से बचें। हिंदी लेखकों को अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए अपनी रचनाओं के लिए कॉपीराइट सुरक्षित करना चाहिए। साहित्यिक नैतिकता को बनाए रखें, और लेखकों और पाठकों दोनों को मौलिकता की वकालत करते हुए साहित्यिक चोरी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। साहित्यिक चोरी के खिलाफ लड़ाई में आलोचक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफसोस की बात है कि प्रकाशन उद्योग में कई संपादक साहित्य की बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की समझ की यह कमी इस मुद्दे की विडंबना को और बढ़ा देती है। मौलिक साहित्यिक कृतियों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, स्तंभों या पत्रिकाओं के संपादक के रूप में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास साहित्य में मजबूत आधार और ज्ञान होना चाहिए। हिंदी साहित्य में साहित्यिक चोरी और कॉपी-पेस्ट की बढ़ती समस्या चिंताजनक है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। साहित्य की विशिष्टता को बनाए रखने और लेखकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना और नैतिक मानकों का पालन करना आवश्यक है। साहित्यिक कृतियों में मौलिकता सुनिश्चित करके हम हिंदी साहित्य के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साहित्यिक चोरी लेखकों की ईमानदारी को कमजोर करती है और साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता को कम करती है। साहित्यिक दुनिया में नवाचार को बढ़ावा देने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए मौलिकता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी लेखकों को नैतिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए अपने काम को रचनात्मक और मौलिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

> **"एक मजबूत समीक्षा संस्कृति की कमी ने साहित्यिक चोरी को साहित्य का एक परेशान करने वाला पहलू बना दिया है। आजकल, कोई भी किसी रचना को उसे बिना किसी जाँच के प्रकाशित करवा सकता है, जिससे ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ मूल लेखक ठगे रह जाते हैं। 'निजी' पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ लेना और उन्हें अपने नाम से प्रकाशित करना आम बात हो गई है। इस व्यवहार को खत्म करने के लिए केवल आलोचना ही अपर्याप्त लगती है। साहित्यिक चोरी सिर्फ़ नए लेखकों या प्रसिद्धि चाहने वालों की ही बैसाखी नहीं है; यहाँ तक कि स्थापित हिंदी लेखक भी दूसरों की रचनाओं में थोड़ा-बहुत बदलाव करके उन्हें अपना बता देते हैं। साहित्यिक चर्चाओं में साहित्यिक चोरी के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें कुछ लेखकों पर प्रसिद्ध पुस्तकों के अंशों को अपनी रचनाओं में शामिल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे अंतत: उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।"**

जगाओ कुछ सीखने की ललक अपने अंदर भी

जुगलबंदी

समीर लाल 'समीर'

लेखक कनाडा निवासी प्रख्यात ब्लॉगर हैं।

कौन कब क्या किससे सीख ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि अगर कुछ सीख लेने की सच्ची ललक मन में ठान लो तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। कई बार तो गुरु प्रकट होता है और वो सिखाने से मना कर देता है, तब पर भी सच्चा सीखने वाला छिप छिप कर सीख लेता है। जैसे कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से सीख लिया था। हालांकि छिप छिप कर सीखने की ट्यूशन फीस में अंगूठा काट कर देना पड़ा। आजकल के जमाने में तो सामने सामने एग्रीमेंट करके सिखाओ तो भी ट्यूशन फीस की वसूली का काम वसूली एजेंसी को देना पड़ता है।

इधर घँसू को यही ज्ञान तिवारी जी ने दे दिया। घँसू को यह बात बहुत जंची। उसने ठान लिया कि वो भी अपने अंदर सीखने की सच्ची ललक जगाएगा और सीख कर मानेगा। मुश्किल बस यह थी कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे सीखना क्या है? बहुत दिन इसी उधेड़ बून में गुजर गए मगर इस यक्ष प्रश्न का कोई हल न मिला। अत: इसी प्रश्न के साथ घँसू पुन: तिवारी जी शरण में पहुंचे। तिवारी जी ने बताया कि यह तो गहन विमर्श का विषय है, शाम को इंतजाम से आओ तब विचार करते हैं।

तिवारी जी यूँ तो सारा दिन पान की दुकान पर बैठे देश और विश्व की हर तरह की समस्याओं पर ज्ञान देते रहते हैं कि आर्थिक मंदी हटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। रोजगार की समस्या का क्या निदान है। रूस यूक्रेन युद्ध कैसे रोका जा सकता है। उनके लिए यह सब मामूली समस्याएं है, जिनके निदान के लिए गहन विमर्श की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर गहरे उतर कर देखें तो वाकई में इन समस्याओं के निदान की बागडोर जिन हाथों में सौंप कर हम सब इनके हल का इंतजार कर रहे हैं, वो खुद अधिकतर बारहवीं पास हैं। ध्यान भटकाने और आपस में लड़वाने की कला में महारथ हासिल करने के सिवाय वो भी तो तिवारी जी की तरह ही ज्ञान बाँट रहे हैं। सौ तीर चलाओ, एक तो निशाने पर लग ही जाएगा। कभी नोट बंद, कभी वोट बंद और कभी किसानों के लिए रोड बंद-सब बंद हो लिया मगर समस्याओं का सिलसिला न बंद हुआ और न बंद होगा। राजनीति की दुकान ही समस्याओं से चलती है - अगर समस्याएं ही न रहीं तो दुकान कैसी?

बहरहाल वापस घँसू की समस्या पर आते हैं। उसे पता था कि तिवारी जी गहन विमर्श की अवस्था में शाम को दो पैग लगाने के बाद आते हैं। अधिकतर लोग इसी अवस्था में पहुँच कर अथाह ज्ञान बांटने में सक्षम हो पाते हैं और वो भी अंग्रेजी में। एक बार तो किसी ने तिवारी जी को रिकार्ड कर लिया था। उनके बोले अंग्रेजी के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनेरी में तक नहीं थे। यह बात जब तिवारी जी को अगली शाम पुन: विमर्श अवस्था में बताई गई तब उन्होंने बताया कि अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनेरी वर्क इन प्रोग्रेस है - धीरे धीरे ही उनकी अज्ञानता के बादल छटेंगे। ऑक्सफोर्ड वाले अच्छा काम कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रगति पथ पर अग्रसर हैं - मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मैं उन्हें उनके कार्य हेतु साधुवाद देता हूँ। रोम भी एक दिन में नहीं बना था - अत: उन्हें वक्त दो।

शाम तय समय पर घँसू बोतल, भुना मुर्गा आदि जरूरी सामग्री लेकर हाजिर हो गए। तिवारी जी यूँ तो पूर्ण शाकाहारी हैं - उन्हें याद नहीं कि कभी भी उन्होंने मांसाहार लिया हो। मगर दो पैग के बाद की अन्य बात भी उन्हें कब याद रही है। अत: दो पैग के बाद मुर्गा भी चला और ज्ञान का प्रवाह भी। विमर्श चाय बनाना सीख कर चाय की दुकान खोलने से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते राजनीति में कदम रखने तक पहुँच कर रुका नहीं। चौथा पैग मुख्य मंत्री की कुर्सी और पाँचवा -अहा! देश प्रधान- छठा- विश्व गुरु!!

सुबह जब घँसू जागे तो सब क्लियर था - राजनीति सीखना है। और यह ऐसा विषय है कि कोई सिखाने को तैयार होगा नहीं तो छिप कर सीखना होगा।

अब घँसू छिप छिप कर- ताक झांक कर सीख रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की हरकतों को छिप छिप कर देख रहे हैं - कभी सर्किट हाउस की खिड़की से तो कभी किसी होटल के कमरे में - नोटस बना रहे हैं। अभी तक घूसखोरी, योन शोषण, झूठ बोलना, मक्कारी, दोगलापन आदि पर काफी अच्छे नोटस तैयार हो गए हैं। आशा है कि अगर इसी लगन के साथ घँसू सीखते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस विधा में महारत हासिल कर एक दिन वो इस देश को दिशा दिखा रहे होंगे और हम सब रेडियो में कान गड़ाए घँसू की मन की बात सुन रहे होंगे।

उम्मीद है कि आज आप में भी कुछ सीखने की ललक जाग ही गई होगी। वरना अपने आस पास वाले किसी तिवारी जी को खोजिए- हर जगह तो हैं वो!

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरतें : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरते। शिकायतों का पूरी गंभीरता और तत्परता से निराकरण किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी जिला अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को आवेदकों से चर्चा कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राचार्य आईटीआई को शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सतत मॉनिटरिंग कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने और आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में वर्चुअल सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

नंदिनी हिरानी एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर बनीं डॉक्टर

बैतूल। बैतूल की होनहार छात्रा नंदिनी धीरज हिरानी ने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली है। उनकी इस सफलता पर परिवार और समाज में हर्ष का माहौल है। नंदिनी ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह मुकाम हासिल कर पूरे सिंधी समाज को गौरवान्वित किया है। नंदिनी सिंधी समाज के अध्यक्ष नरेंद्र हिरानी के वरिष्ठ भ्राता एवं पिंजामल ऐशीमल के संचालक नवल किशोर हिरानी की पोती हैं। उनके पिता धीरज हिरानी युवा व्यवसायी और समाजसेवी हैं। परिजनों के अनुसार नंदिनी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है और उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया और माता-पिता अंजली- धीरज हिराणी सहित परिजनों के मार्गदर्शन में सफलता पाई। नंदिनी की इस उपलब्धि पर माता अंजली, पिता धीरज हिराणी परिजनों सहित समाज के गणमान्य जनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और उम्मीद जताई है कि वे एक सफल चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करेंगी। नंदिनी की सफलता से सिंधी समाज और परिजनों में जश्न का हर्ष का माहौल बना हुआ है।

शॉर्ट सर्किट से घर में फैली आग, सामान जलकर खाक

बैतूल। शनिवार रात लगभग 11 बजे मुलताई क्षेत्र के पटेल वार्ड स्थित पवन कुमार के पक्के मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मुलताई नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और तत्परता से आग पर काबू पाया। पवन कुमार ने बताया कि बिजली बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते मकान में रखा फ्रिज, टीवी सहित अन्य घरेलू सामान में आग लग गई। आग लगते ही तुरंत ही दमकल को बुलाया गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पवन ने बताया कि आग लगने के बाद घर के लोग घर से बाहर भाग गए। इधर धमाके के साथ टीवी फूट गया और फ्रिज में से भी तेज आवाज आई और वह भी जल गया। घर में रखा किराना, कपड़े, सहित अन्य समान भी पूरी तरह जल गया। मामले की शिकायत रात को ही पुलिस से की गई। थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि मामले में आगजनी कायम कर जांच शुरू की गई है।

मालवी सेन समाज का होली मिलन समारोह 19 मार्च को

बैतूल। मालवी सेन समाज संगठन द्वारा 19 मार्च को दोपहर 11 बजे से दुर्गा वार्ड क्रमांक 3, बड़ी टावर लाइन के पास स्थित श्री चमत्कारी नंदेश्वर शिव धाम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष द्वारा समाज जनों एवं मालवी ग्रुप के सभी सदस्यों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

ताप्ती सरोवर से हटाई जाएंगी 17 दुकानें

न्यायालय के आदेश से होगा 17 दुकानों का पुनर्वास

बैतूल/मुलताई। ताप्ती सौंदर्यीकरण में बाधक ताप्ती सरोवर के तट पर स्थित जर्जर हो गई 17 दुकानों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए ताप्ती श्रद्धालुओं एवं ताप्ती सरोवर तट के दुकानदारों को भी बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 17 दुकानदारों के लिए 6 से 9 माह में पुनर्वास योजना बनाए और नए आवंटन स्थान पर दुकानों का निर्माण करने के बाद याचिकाकर्ताओं को वर्तमान परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसका उपयोग राज्य सरकार ताप्ती सरोवर के पुनर्विकास के लिए कर सकती है, जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होने के कारण एक पवित्र स्थल है। उक्त आदेश को ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है और जिससे नगर की जनता और व्यापारी दोनों मे ही प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ, दिए याचिका निपटारे के आदेश- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने 13 मार्च, 2025 को रिट याचिका संख्या 19441/2014 दीपक वर्मा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्य उपस्थिति दिव्य कृष्ण बिलैया- याचिकाकर्ताओं के वकील वेद प्रकाश तिवारी-राज्य के सरकारी वकील, आदेश- कलेक्टर, जिला बैतूल के निर्देश पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर, जिला बैतूल ने छह से नौ महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को पुनर्वसित करने पर सहमति व्यक्त की है और उक्त संचार संबंधित उपविभागीय अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक अ.वि.अ./2025/572 दिनांक 13/03/2025 द्वारा किया गया है। इन तथ्यों और विद्वान सरकारी वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, आगे कोई निर्णय शेष नहीं है। पुनर्वास योजना बनाने और नए आवंटित स्थान पर दुकानों का निर्माण करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को वर्तमान परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है, जिसका उपयोग राज्य सरकार ताप्ती सरोवर के पुनर्विकास के लिए कर सकती है, जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होने के कारण एक पवित्र स्थान है। न्यायालय ने कहा उपर्युक्त शर्तों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

जर्जर खतरनाक हो गई थी 17 दुकाने- ताप्ती तट पर स्थित वर्षों पुरानी 17 दुकानो की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। 17 जुलाई 2021 को नगर पालिका अधिकारी एवं लोक निर्माण अधिकारी ने 17 दुकानों की जर्जर स्थिति की जांच की, जांच करने पहुंचे अमले ने पाया कि 17 दुकानों के छत को बांस से ठोकने से छत टूटने लगा था। लोक निर्माण अधिकारी ने 17 दुकानों की स्थिति को चिंताजनक बताया है। दुकानों की स्थिति अत्यंत खतरनाक होती जा रही है। लंबे समय से नगरवासी ताप्ती तट पर स्थित 17 दुकानों को हटाने की मांग करते आ रहे हैं, ताकि ताप्ती सरोवर का सौंदर्य मुख्य मार्ग से दिखाई दे सके, किंतु व्यापारी चाहते हैं कि 17 दुकानों के दुकानदारों को अन्य स्थान पर बसाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही दुकानों को तोडा जाना चाहिए। न्यायालय के इस फैसले ने सभी पक्षों को संतुष्ट कर दिया है।

कहां होगा 17 दुकानों का पुनर्वास

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यह तो तय हो गया है कि ताप्ती सौंदर्यीकरण में बाधक बनी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी 17 दुकानें हटाई जाएगी। किंतु बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय के आदेश के तहत समय अवधि में दुकानदारों का पुनर्वास कहां होगा। पूर्व में यह माना जा रहा था कि 17 दुकानों को हटाकर दुकानदारों को पुराने स्वास्थ्य केंद्र की भूमि पर बसाया जा सकता है। किंतु उक्त भूमि को अब गीता भवन के लिए सुरक्षित रखे जाने की चर्चाएं हैं। बताया गया है कि लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाले गीता भवन प्रोजेक्ट भी शासन की बड़ी परियोजना है। इसके बाद टेकाडे वाला हिंदी स्कूल एवं पूर्व प्राथमिक कन्या शाला जहां पर भक्त निवास एवं कंपलेक्स प्रस्तावित है उक्त स्थान का भी उपयोग व्यापारियों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।

इनका कहना -

न्यायालय के उक्त आदेश का नगर पालिका अक्षरशः पालन करेगी। हमारा उद्देश्य ताप्ती सौंदर्यीकरण के साथ ही व्यापारियों के व्यवसाय, व्यापार और आज जीविका को सुनिश्चित करना भी था, जो कि न्यायालय के आदेश से किया जाएगा। जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका सवाल है यह भुमी बड़े प्रोजेक्ट गीता भवन के लिए सुरक्षित रखी जा रही है, इसके अलावा प्राथमिक कन्या शाला या टेकने वाले स्कूल भूमि पर उक्त विस्थापन की योजना को किया जा सकता है अन्य विकल्प भी तलासे जा सकते हैं।

- वर्षा गढ़ेकर,
अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मुलताई

बैतूल ऑयल लिमिटेड के टैंक में मिले दो कर्मचारियों के शव

परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया चक्काजाम, प्रशासन की समझाइश के बाद माने परिजन

बैतूल। बैतूल ऑयल लिमिटेड में वाटर टैंक सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और अन्य लोगों ने जिला अस्पताल के सामने चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये थे। दरअसल बैतूल ऑयल लिमिटेड में टैंक की सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई। शनिवार रात की शिफ्ट में शायद मजदूर टैंक में उतरे थे जिसके कुछ देर बाद दोनों टैंक में पड़े मिले। जिसके बाद कंपनी के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि टैंक की नियमित सफाई हर दो महीने में की जाती है। घटना रात की शिफ्ट (4 से 12 बजे) के दौरान हुई। शिफ्ट बदलने के समय दूसरे रिलीवर कर्मचारियों को कैलाश पानकर (53) और दयाराम नरवरे (56) टैंक में मृत मिले। मौका पंचनामा के बाद शवों को पोस्टमार्ट्म के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए उचित मुआवजे की मांग को लेकर जिला अस्पताल एवं नेहरू पार्क के सामने चक्काजाम लगा दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन मौके पर पहुंच गया। एएसपी कमला जोशी, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, एसडीएम राजीव कहार समेत अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी। काफी मान-मनौव्वल के बाद परिजन किसी तरह माने। फिलहाल नपा बैतूल द्वारा संबल योजना के तहत मृतकों के परिजनों को अंत्येष्टि राशि 5 हजार रुपये दी गई है। योजना के तहत जांच के बाद अन्य प्रावधानों के तहत मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। इस संबंध में एएसपी कमला जोशी ने बताया कि मृतकों के परिजनों और मिल प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद मामले का निराकरण हो गया है और शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, पुलिस की जांच जारी है।

इनका कहना -

दो कर्मचारियों के शव वॉटर टैंक में मिले थे, शनिवार रात 12 बजे शिफ्ट बदलने दौरान दूसरे रिलीवर को ये दोनों कर्मचारियों के ना मिलने पर आसपास देखा, तो वॉटर टैंक में दोनों के शव मिले थे। मृतकों के परिजनों को पीएफ, बीमा तथा अन्य क्लेम आदि की राशि मिलाकर लगभग दस लाख तक की राशि मिलेगी, जिसका लिखित में आश्वासन भी परिजनों को दिया गया है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंत्येष्टि कर दी गई।

-अजय मिश्रा,
एच. आर. मैनेजर, बैतूल ऑयल मिल

बैतूल जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव : केंद्रीय राज्य मंत्री

जिला चिकित्सालय को प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों का किया लोकार्पण

बैतूल। केन्द्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गादास उइके ने जिला चिकित्सालय को प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला अस्पताल में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उईके ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम द्वारा अपने सीएसआर पहल के अंतर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय बैतूल को चिकित्सकीय उपकरण प्रदान किए गए है। जिससे अब जिले के मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उईके ने पावर ग्रिड के अधिकारियों से जिला अस्पताल में डायलिसिस की 10 मशीन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया, ताकि जिला अस्पताल में मरीजों को नागपुर उपचार के लिए न जाना पड़े। कार्यक्रम के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने अतिथियों को सम्मानित भी किया। लोकार्पण कार्यक्रम में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे, जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, मुख्य महाप्रबंधक पावरग्रिड पश्चिमी क्षेत्र-2 संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक खंडवा, बैतूल डीके कर्मा, सीएमएचओ डॉ. रविकांत उइके, सिविल सर्जन डॉ.जगदीश घोरे सहित शासकीय जिला चिकित्सालय और पावर ग्रिड के अधिकारी उपस्थित रहे।

चिकित्सकीय उपकरणों को देखा- कार्यक्रम के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उईके, विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जिला अस्पताल को प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों को देखा। सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उईके ने भोजन शाला में पहुंच कर रोटी मेकर मशीन को देखा। इसके बाद ईसीएचओ एंड टीएमटी कक्ष में इकोकार्डियोग्राफी मशीन तथा ऑपरेशन थिएटर में विडियो एंडोस्कोपी मशीन की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम द्वारा अपने सीएसआर पहल के अंतर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय बैतूल को 97 लाख 59 हजार 431 रुपए की लागत के चिकित्सीय उपकरण प्रदान किए गए है। चिकित्सकीय उपकरणों में विडियो एंडोस्कोपी मशीन, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, टीएमटी मशीन, रोटी मेकर मशीन एवं मोर्चरी कैबिनेट शामिल हैं।

मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा रेफर- बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जब तक अत्याधुनिक मशीनें नहीं होगी तब तक मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिला अस्पताल में अब चिकित्सकीय उपकरण होने से मरीज को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा और उन्हें भोपाल या नागपुर उपचार के लिए रेफर नहीं करना होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीएमएचओ से जिला अस्पताल को मिले चिकित्सकीय उपकरणों से मरीज को बेहतर उपचार दिलाने की बात कही। इसके अलावा बैतूल विधायक श्री खंडेलवाल ने मरीजों को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने का अनुरोध किया।

उपकरण मिलना स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम- आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे ने कहा कि जिला अस्पताल को चिकित्सकीय उपकरण मिलना स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। अब जिला अस्पताल में एंडोस्कोपी मशीन होने से पेट के रोग, कोई बच्चा गले में कुछ निगल जाए तो उसका पता लगाने एवं उसके निदान में मदद मिलेगी और मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टरों को इन मशीनों का बेहतर संचालन करने और मरीज को इसका लाभ दिए जाने की बात कही। इसके लिए डॉक्टरों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीएमएचओ डॉ.रविकांत उइके ने कहा कि पहले जिला अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरण नहीं होने से मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था। लेकिन अब विडियो एंडोस्कोपी मशीन, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, टीएमटी मशीन, रोटी मेकर मशीन एवं मोर्चरी कैबिनेट उपकरण मिलने से मरीज का जिला अस्पताल में ही उपचार किया जाएगा।

बच्चों और युवाओं ने जमकर खेली होली, रंग-भंग और तरंग की रही धूम

जिलेभर में शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मना होली पर्व

बैतूल। होली दहन के दूसरे दिन धुलेंडी पर्व जिले भर में सादगी के साथ मनाया गया। सभी ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। हुरियारों की टोली सुबह से ही दिखाई देने लगी थी। गली-मोहल्ले में सुबह से ही लोगों ने गुलाल खेलने का दौर शुरू कर दिया था। रंगों के पर्व को लेकर बड़े लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया। उन्होंने गुलाल से होली मनाई, जबकि युवा एवं बच्चों ने एक-दूसरे पर जमकर रंग बरसाया। रंगों की मस्ती में हर कोई झूमता नजर आया। उत्साह, उमंग और उल्लास के इस पर्व का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। टोलियां बनाकर जहां युवाओं ने हुल्लड़ मस्ती की, वहीं महिलाएं-युवतियां और बच्चों ने भी होली के रंगों का जमकर लुत्फ उठाया। इससे पूर्व गुरूवार रात्रि होली समितियों द्वारा होलिका दहन किया गया। होली दहन के साथ-साथ रंग-गुलाल की फुहारें भी बरसने लगी। जगह-जगह उड़ते रंग गुलाल की फुहारों से पूरा वातावरण रंगमय हो गया।

सूखे रंग रही पहली पसंद- होली में सबसे ज्यादा सूखे रंग लोगों की पसंद रही, वहीं रासायनिक रंगों से लोगों को परहेज करते देखा गया। बुजूर्ग-युवाओं और बच्चों ने गुलाल और हर्बल रंगों से होली मनाई। इसके साथ ही काफी हद तक पानी की भी बचत की। हालांकि हुलियारों ने पहले से ही होली की तैयारी कर रखी थी। बच्चों और बड़ो के अलावा महिलाओं और युवतियों ने भी धुरेंडी पर एक-दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई।

बच्चों ने खूब खेली होली- रंग-बिरंगे रंगों के पर्व होली को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग का माहौल छोटे-छोटे बच्चों में देखा गया। पिचकारी में रंग भरकर बच्चे एक-दूसरे को लगा रहे थे। पिचकारी में रंग भरकर बच्चे अपने दोस्तों को लगाने के लिए एक-दूसरे के पीछे भागते नजर आए। बच्चों में होली का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके साथ ही म्यूजिक पर बच्चे खूब नाचे और होली मनाई।

रंग-भंग, ठंडाई और तरंग की रही धूम- होली पर्व पर रंग-भंग और तरंग की खूब धूम रही। लोगों ने जहां जमकर रंग खेला, वहीं भंग, ठंडाई भी चखी और बैंड-बाजे की धून पर जमकर थिरके। जगह-जगह युवाओं की टोली नाचते और झूमते नजर आई। होली के पर्व पर युवाओं ने विशेष तैयारियां कर रखी थी। इसके साथ ही युवाओं ने बड़े बुजूर्गो के साथ भी होली खेली। बड़े-बुजूर्गो को गुलाल का तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया।

परीक्षार्थी रहे रंगों से दूर- रंगों के इस पर्व से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों ने परहेज की। दरअसल परीक्षा शुरू होने से विद्यार्थी रंगों से दूर नजर आए। वहीं बच्चों और बुजूर्गो ने जमकर होली का लुत्फ उठाया, तो दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के हाथों में रंगों की जगह पुस्तके नजर आई। विद्यार्थी इस पर्व का लुत्फ उठाने के लिए बेहद उत्सुक नजर तो आए लेकिन परीक्षा के कारण वे दूर ही रहे।

केन्द्रीय राज्यमंत्री, विधायक और नपाध्यक्ष ने भी खेली होली

बैतूल। रंगोत्सव धुलेंडी पर्व जिलेभर में धूमधम से मनाया गया। शहरवासियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी खूब होली खेली। जनप्रतिनिधियों ने भी आमजनों और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर होली मिलन में जमकर रंग-गुलाल उड़ाया। इसी तारतम्य में बैतूल में केन्द्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, नपाध्यक्ष बैतूल पार्वतीबाई बारस्कर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ मिलकर होली पर्व मनाया। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री उइके, विधायकगण श्री खंडेलवाल एवं डॉ. पंडाग्रे के निवास पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के कार्यालय पर भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के लोग और भाजपाई शामिल हुए। मिलन समारोह में लोगों ने खूब रंग-गुलाल उडाया और जमकर झूमे। वहीं आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने भी समर्थकों संग लोगों को रंग-गुलाल लगाया।

पुलिस ने दूसरे दिन खेली होली, जमकर उड़ाया रंग-गुलाल

बैतूल- शनिवार पुलिसकर्मियों ने होली का त्योहार मनाया। पुलिसकर्मी और अधिकारी रंग में रंगे नजर आने लगे थे। गाजे-बाजे के साथ कोतवाली और गंज थाने के समस्त स्टाफ ने जमकर होली खेली। सभी पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम के पीछे स्थित पुलिस लाईन में एकत्रित हुए। जहाँ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया एवं एएसपी कमला जोशी, आर.आई. दिनेश मर्सकोले की उपस्थिति में अपने वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ होली मनाने को लेकर साउंड सिस्टम भी लगाया था। संगीत की धुन पर पुलिस कर्मी जमकर झूमते नजर आए। पुलिसकर्मियों के साथ-साथ उनके परिवार के लोगों ने भी होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी थाने और चौकियों में अपने परिजनों को छोड़कर पुलिसकर्मी अपने फर्ज पर तैनात थे, ताकि आमजन शांति और सद्भाव के साथ होली का पर्व मना सकें। धुरेड़ी के बाद शनिवार को पुलिसकर्मियों ने होली का पर्व मनाया।

आयोजन

सुधीर नायक

(लेखक मंत्रालय सेवा अधिकारी/ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं)

आखिर पूजापाठ का सहारा क्यों ले रहे हैं शासकीय कर्मचारी?

इ सी साल जनवरी में अध्यापक संगठनों द्वारा अंबेडकर मैदान में 7 दिवसीय भागवत कथा करायी गई। 4 मार्च को मंत्रालय में मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय परिसर में सुंदरकाण्ड पाठ रखा गया। 4 मार्च को ही विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा विधानसभा परिसर में 108 हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। उसी तारीख को मुरैना में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा भी सुंदर काण्ड पाठ रखा गया। इन सब घटनाओं से यह प्रश्न उभरता है कि कर्मचारी संगठन अपने परंपरागत शांतिपूर्ण तरीकों-ज्ञापन,वार्ता,अभ्यावेदन, प्रदर्शन इत्यादि को छोड़कर पूजापाठ का सहारा लेने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं?

दरअसल प्रशासन तंत्र में आ चुकी गहरी असंवेदनशीलता,अहंकार, अकर्मण्यता अनिर्णयता और टालमटोली की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। कर्मचारी संगठनों को लगता है कि शायद भगवान के नाम पर ही उनकी बात सुन ली जाए। एक जमाना था जब केवल काली पट्टी लगाने का भी संज्ञान लिया जाता था। छोटी-मोटी समस्याएं तो काली पट्टी लगाने से ही हल हो जाती थी। केवल आंदोलन का नोटिस देने से ही वार्ता के लिए बुला लिया जाता था और अकसर आंदोलन की नौबत ही नहीं आ पाती थी। वार्ता में ही काफ़ी चीजें निपट जाती थी। आंदोलन इस बात का संकेत होता था कि हम कुछ सुनाना चाहते हैं। अब यह एक अघोषित निर्णय हो चुका है कि आंदोलनरत कर्मचारियों से बात नहीं की जाएगी और बिना आंदोलन के भी बात नहीं की जायेगी तथा आंदोलन के बाद तो की ही नहीं जायेगी। तो फिर बात कब होगी? लोक प्रशासन में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कर्मचारी और प्रबंधन के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक सुसंचालित प्रणाली होनी चाहिए। सतत संवाद चलना चाहिए। तभी सुशासन का लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन शासन में इस सिद्धांत की घोर उपेक्षा हो रही है। शासन और कर्मचारियों के बीच जितने पुल थे सब ध्वस्त हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण था, जिसे वर्ष 2003 में अकारण ही समाप्त कर दिया गया।

परामर्शदात्री समितियां अब केवल नाम के लिए रह गयी हैं। उनकी बैठकें ही नहीं होती। बड़ी जोर आजमाइश के बाद एकाध बैठक हो भी गयी तो उस बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन नहीं होता। हर कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर इस प्रावधान का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कागज़ों में ये समितियां गठित हैं लेकिन इनकी बैठकें नहीं होतीं। जबकि इन समितियों का गठन राज्य की मुकदमा नीति के तहत किया गया था ताकि मुकदमों में कमी आये और सरकार का बेवजह मुकदमों में हो रहा खर्च कम हो। विधानसभा में याचिका समिति है उसकी भी कर्मचारी समस्या निवारण की दिशा में कोई उल्लेखनीय भूमिका अभी तक देखने सुनने में नहीं आयी। कर्मचारी कल्याण समिति के गठन का प्रयोग किया गया था वह भी लगभग विफल रहा। एक तो अधिकांश समय उस समिति के पद खाली रहते हैं। चुनाव के समय एक डेढ़ साल के लिए नियुक्ति होती है। फिर उस समिति को पत्र लिखने के अलावा कोई अधिकार नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल के प्रारंभिक वर्षों में कर्मचारी मामलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव की नियुक्ति की गयी। उस समय यह प्रणाली कारगर सिद्ध हुई थी। बाद में यह प्रणाली निष्क्रिय हो गयी या कर दी गयी। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से हम मांग करते आ रहे हैं कि महिला आयोग,मानवाधिकार आयोग इत्यादि की भांति विधानसभा में पारित अधिनियम के माध्यम से एक स्थायी कर्मचारी आयोग गठित होना चाहिए जो कर्मचारी समस्याओं को निरंतर सुनता रहे और उसका न्यायोचित निराकरण करता रहे। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को पुन: स्थापित किया जाना अब जरूरी हो गया है। छोटी छोटी बिल्कुल न्यायसंगत चीजों का भी निराकरण न होने से न्यायालयों में कर्मचारी और शासन के बीच हजारों मुकदमे लंबित हैं जिनपर शासन का करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च हो रहा है। अधिकांश मामलों में शासन हारता है। ये मुकदमे केवल अनिर्णय और टालामटोली की प्रवृत्ति के कारण उदभूत होते हैं। जिन मामलों में बिल्कुल सुस्पष्ट नियम विद्यमान हैं उन मामलों में भी उच्च स्तर से मार्गदर्शन मांगने का चलन आम हो चुका है। उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच मामला झूलता रहता है। जबकि सबकी शक्तियां सुस्पष्ट रूप से नियमों में लिखी हुई हैं। अनिर्णय और टालमटोली का यह आलम है कि कोर्ट का निर्णय कर्मचारी के पक्ष में आ जाने के बाद उसे भरसक लटकाया जाता है। हर मामले में जितने भी स्तर पर अपीलें संभव हो सकती हैं उतनी अपीलें की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक निर्णय से बचा जा सके। प्रशासनिक तंत्र की इस प्रवृत्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी नंबर 29852/2009 में निर्णय दिनांक 31/10/2009 पारित कर फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि हर बात के लिए आम कर्मचारी को कोर्ट जाने के लिए बाध्य करना और फिर हर न्यायालयीन निर्णय पर सरकार द्वारा अपील करना उचित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने और विधि विभाग ने उक्त न्यायालयीन निर्णय का पालन करने के लिए परिपत्र जारी कर औपचारिकता निभा दी पर यथास्थिति बनी हुई है।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक (सुशीला देवी 20876/2016(सुशीलादेवी प्रकरण) में पारित निर्णय दिनांक 04/01/2017 में निर्देश दिए कि यदि किसी एक कर्मचारी के मामले में न्यायालयीन निर्णय आता है तो उसे अन्य सभी समान रूप से पीड़ित कर्मचारियों के लिए मान्य किया जाना चाहिए। मतलब हर पीड़ित कर्मचारी को न्यायालय जाने की बाध्यता न रहे। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर परिपत्र जारी किया था। परंतु आज भी हर पीड़ित कर्मचारी को पृथक से न्यायालय जाना पड़ता है उसे पूर्व उदाहरण का लाभ नहीं मिलता। अभी फिर उच्च न्यायालय ने रिट अपील क्र. 114/2025 में पारित एक निर्णय दि. 22/01/ 2025 में बिना सोचे समझे हर बात में अपील करने की प्रवृत्ति को लेकर पुन: फटकार लगाई है। इस पर पुन: परिपत्र जारी कर दिया गया है।

कुछ लोगों का मानना है कि कर्मचारियों की बात न सुनी जाने के लिए कर्मचारी संगठनों की फूट और संगठनों के बीच के आपसी झगड़े उत्तरदायी हैं। लेकिन यह केवल अर्द्धसत्य ही है। वास्तविकता यह है कि कर्मचारी संगठन (अथवा किसी भी तरह के अशासकीय संगठन) के पदाधिकारियों की वैधानिकता की जांच करने के लिए न कोई नियम हैं और न कोई एजेंसी। मध्यप्रदेश के गठन के 69 साल बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। अशासकीय संगठनों के पंजीयन और उनपर नियंत्रण रखने के लिए पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं नामक विधिक संस्था स्थापित है। परंतु पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा कर चुका है कि उसके द्वारा पंजीकृत किसी संगठन के पदाधिकारियों की वैधानिकता की जांच करने की शक्तियां उसके पास नहीं हैं। इस नियम शून्यता का लाभ उठाकर कर्मचारी संगठनों सहित तमाम अशासकीय संगठनों में कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से पदाधिकारी बन जाता है और संगठनों को मूल उद्देश्य से भटकाकर निजी हित में उपयोग करने लगता है। ऐसे अवैधानिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी संगठनों के अधिकांश झगड़े नियमों की इसी विसंगति से उदभूत हो रहे हैं। झगड़े बने रहे शायद इसीलिए यह विसंगति दूर नहीं हो पा रही है।

सिद्ध महाराज पर होली मिलन समारोह

सुबह सवेरे सोहागपुर। मप्र जन अभियान परिषद सोहागपुर के तत्वावधान में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृव क्षमता विकास पाठ्यक्रम के तहत छात्र एवं छात्राओं ने विकासखंड समन्वयक किशोर कड़ोले के मार्गदर्शन में होली पावन पर्व के उपलक्ष्य में सामुहिक होली मिलन समारोह पवित्र सिद्ध महाराज आयोजित किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने सर्व प्रथम एक दूसरे को गुलाल लगा कर शुभकामनाएं दी। बाद में मिष्ठान गुजिया पपड़ी से एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसी अवसर पर सभी ने नशामुक्ति शपथ ग्रहण ली। भोजन प्रसादी ग्रहण के उपरांत पूरे परिसर की झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में एम एस डब्लू,बी एम डब्लू के छात्र,छात्राएं हरिदास दिवाकर, सौरभ शर्मा, सौरभ बेलवंशी, आयुषी कुशवाहा, शिवानी मेहरा आदि स्थानीय ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। उल्लेखनीय है कि सिद्ध महाराज पर बंट वृक्ष पवित्रता एवं आर्कषण केन्द्र है। इसको देखने दूर-दराज के श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से सौजन्य भेंट की।

पीसीसी चीफ जीतू बोले-एमपी में कानून खत्म हो गया

भोपाल (नप्र)। इंदौर में तुकोगंज थाने के टीआई को वकीलों द्वारा दौड़ा-दौड़ा कर पीटने, मऊगंज में आदिवासियों द्वारा एक एएसआई की हत्या करने और मंडला में एक आदिवासी का नक्सली बताकर कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामलों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र सरकार को घेरा है।

जीतू पटवारी ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं। ऐसा पहला प्रदेश बन गया है, जहां पर पुलिस की पिटाई लगातार और बार-बार होती है।

पिछले तीन दिनों में तीन जगह पुलिस पिटी है। इंदौर में वकीलों ने एक टीआई यादव जी को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। वकीलों का आरोप है कि यादव जी टीआई साहब दारू पीकर शराब के नशे में पहुंचे थे।

मऊगंज में पुलिस की हत्या हो जाना यह क्या मैसेज है? फिर मंडला में एक आदिवासी की पुलिस ने नक्सली बताकर हत्या कर दी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जी मध्य प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया नहीं बची।

पुलिस का काम अवैध धंधे चलाना हो गया- पटवारी ने कहा, एमपी ऐसा पहला प्रदेश है, जहां पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया है। एक जगह घटना नहीं होती, हर शहर, हर जिले की यह स्थिति है। मतलब यह है कि गृहमंत्री का काम पूरा फेल हो गया। हमने बार-बार गृहमंत्री जी से मांग की थी कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसका कोई एकमात्र दोषी है तो वह आप हैं।

अप्रैल में जारी हो सकता है 7 हजार आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन, पीईबी ने शुरू की तैयारी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 7,400 पुलिस आरक्षकों की भर्ती का परीक्षा परिणाम पिछले सप्ताह जारी होने के बाद अब करीब 7000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो सकती है। कर्मचारी चयन मंडल (पीईबी) इसकी तैयारी कर रहा है। विज्ञापन जारी होने के बाद लिखित परीक्षा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी।

दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर वर्ष के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है। यानी अगले वर्ष इन पुलिस आरक्षकों की सेवाएं मिलने लगेंगी। अभी तक आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लगभग डेढ़ वर्ष लग रहे थे। इस कारण रिक्त पदों के विरुद्ध प्रति वर्ष भर्ती का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा था।

भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार पीईबी पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मंडल के पास अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण अधिक समय लग रहा था। भर्ती के लिए पीईबी कैलेंडर तैयार कर रहा है।

आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी है थाने की संख्या

बता दें, प्रदेश में 1 लाख 26 हजार स्वीकृत पदों में से लगभग 95 हजार आरक्षक ही पदस्थ हैं। जिस तरह से आबादी और अपराध बढ़े हैं, उसे देखते हुए कम से कम डेढ़ लाख पुलिस आरक्षकों की आवश्यकता है। जिला पुलिस बल के 960 थाने हैं। अपराध और आबादी बढ़ने के कारण थानों की संख्या भी बढ़ाई जानी है, लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण नए थाने नहीं बनाए जा रहे हैं। छोटे थाने के लिए कम से कम 35 और बड़े थाने के लिए 60 से 70 पुलिसकर्मी चाहिए। आरक्षकों की भर्ती से नए थाने खोलना भी आसान हो जाएगा। उप निरीक्षकों के लगभग 500 पदों पर भी अगले माह भर्ती प्रारंभ कर इसी वर्ष परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है।

इस वर्ष ही जारी होंगे परीक्षा परिणाम

पीईबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि इस बार ऐसी तैयारी है कि इस वर्ष ही आरक्षकों और उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएं।

पीतांबरा पीठ के आचार्य पं.ओम नारायण शास्त्री जी का ब्रम्हलोक गमन

भोपाल। पीतांबरा पीठ दतिया के आचार्य पंडित श्री ओम नारायण शास्त्री जी का गुरुवार पूर्णमासी के दिन सांय 5.30 बजे ब्रम्हलोक गमन हो गया। पंडित श्री शास्त्री संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ पीतांबरा पीठ दतिया के आचार्य भी थे। वे राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज जी के चरण सेवक उनके परम शिष्य थे। आचार्य जी लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन का समाचार पाकर समूचे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। शिष्यों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आचार्य जी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वे पीठ के स्तंभ थे और सभी गुरु सेवकों के मार्गदर्शक थे। उनके मार्गदर्शन में कई साधकों को दीक्षा प्रदान की गई। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पीठ के लिए समर्पित कर दिया था। आचार्य जी की अंतिम यात्रा उनके निज निवास पकौड़िया महादेव से नए ताल मुक्ति धाम के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी।

टीकाकरण, बच्चों की गंभीर बीमारियों से सुरक्षा कर बढ़ाता है उनकी इम्युनिटी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वस्थ बचपन, सशक्त भविष्य का आधार है। टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेशवासियों से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत के लिए टीकाकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहभागिता करने का संकल्प लेने का आव्हान किया है।

एमपी में 18-19 मार्च को बारिश, लुढ़केगा पारा

भोपाल (नप्र)। तेज गर्मी के बीच मध्यप्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। अगले दो दिन यानी, 16-17 मार्च को दिन-रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, जबकि 18-19 मार्च को जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, शहडोल और ग्वालियर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। खासकर 19 मार्च को पूर्वी हिस्सा भीगेगा।प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रातें भी गर्म हैं। हालांकि, पिछले 3 दिन से प्रदेश के कुछ शहरों में मौसम बदला हुआ है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज गर्मी है, लेकिन अगले दो दिन में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी।

चाय की दुकान पर काम करने वाले 22 साल के लड़के ने की 20 चोरियां, डेढ़ करोड़ का माल उड़ाया

बुरहानपुर (नप्र)। ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करने और अपराध की दुनिया में अपना नाम करने की चाहत में 22 साल उम्र तक आते-आते भिवंडी महाराष्ट्र के नदीम खान ने चोरी की बीस वारदातों को अंजाम देकर करीब डेढ़ करोड़ का माल उड़ा डाला।

यह अलग बात है कि हर चोरी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अधिकांश नकदी व आभूषण बरामद कर लिए। रविवार को एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश और सीएसपी गौरव पाटिल ने सात मार्च को पांडुमल चौराहे के पास हुई चोरी का राजफाश किया तो यह कहानी सामने आई।

पुलिस ने आरोपित नदीम के पास से 45,500 रुपये नकद और 13 लाख 54 हजार 500 रुपये के सोने, चांदी व डायमंड के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। चोरी गए आभूषण सात दिन के अंदर बरामद होने पर पीड़ित राजरानी मेहता ने पुलिस का आभार जताया।

दस हजार का इनाम किया था घोषित- एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया चोरी की इस वारदात को सुलझाने के लिए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने चोर की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी।

जिसमें शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल पंवार, एसआई हेमेन्द्र सिंह चौहान, एएसआई देवेन्द्र पाटील, मेहफूज अली, सीसीटीवी कंट्रोल रूप में एएसआई मुकररीम खान आदि को शामिल किया गया था। दूसरी ओर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे।

चाय की होटल में करता था काम- पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर मुखबिरों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस तरह का एक व्यक्ति चाय की दुकान में काम करता है और नया मोहल्ला में रहता है। संदेह के आधार पर पुलिस ने नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया।बताया जाता है कि नदीम रहतपुर शांतिनगर भिवंडी जिला ठाणे में रहते हुए कम उम्र में ही 18 से ज्यादा चोरियां कर ली थीं। पुलिस उससे एक करोड़ से ज्यादा के आभूषण व नकदी बरामद कर चुकी थी। लगभग हर थाने में उसकी तस्वीर लग चुकी थी, जिसके चलते कुछ समय से वह बुरहानपुर में आकर रहने लगा था और दिखावे के लिए चाय की दुकान में काम करता था। पहले वह सूने मकानों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदात करता था।

आगर मालवा में ढाई साल के बच्चे का अपहरण, मंदिर जाते वक्त मौसेरी बहन से 5 लोगों ने छीना

मां को पति पर अपहरण का शक, पति-पत्नी दो साल से अलग हैं

आगर मालवा (नप्र)। कोतवाली थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन से आए पांच लोगों ने ढाई वर्षीय भव्यांश का अपहरण कर लिया। वह मौसेरी बहन रोशनी के साथ मंदिर जा रहा था।

इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने रोशनी से झूमाझटकी भी की। रोशनी ने कुछ दूर तक वाहन का पीछा भी किया, लेकिन वाहन बड़ोद रोड की तरफ निकल गया। सभी लोगों ने चेहरे ढंक रखे थे। बच्चे के अपहरण की जानकारी मां व अन्य स्वजन को लगी तो कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने अपहरण की शिकायत की।

पहले भी हुआ था बच्चे का अपहरण

मां रीना का कहना है कि अपहरण की घटना के पीछे पति का हाथ हो सकता है। एक वर्ष पहले भी वह बच्चे को जबरदस्ती ले गया था। उस समय पुलिस ने बंगाल से बच्चा दस्तयाब किया था।रविवार को अपहरण के समय रोशनी से एक बदमाश ने कहा था कि तुम घर जाओ, बच्चा हम ले जा रहे हैं। रोशनी का कहना है कि वह आवाज बच्चे के पिता जैसी लग रही थी।

अलग-अलग रहते हैं पति-पत्नी

रीना ने बताया कि वह पति से दो वर्ष से अलग रह रही है। उसने पति के खिलाफ आगर-मालवा के महिला थाने में वर्ष 2024 में दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करवाया था। इस प्रकरण की सुनवाई 25 मार्च को होनी है।

उस समय केस दर्ज करवाने के बाद रीना बच्चे के साथ कोतवाली थाने से एसडीओपी कार्यालय जा रही थी, तभी आगर के साईं मंदिर के पास से पति भव्यांश को छीनकर इंदौर ले गया था, जहां से हवाई जहाज से उसे बंगाल ले गया था।

पति पर लगाया अपहरण का आरोप

बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने पति पर ही अपहरण की शंका प्रकट की है। पुलिस टीम तलाश कर रही है।

अनिल मालवीय, नगर निरीक्षक कोतवाली थाना, आगर-मालवा

राइट क्लिक

हिंदी व क्षेत्रीय भाषा में तकनीकी शिक्षा और आजीविका का सवाल

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

तमिलनाडु की डीएमके सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार के बीच जारी 'भाषा युद्ध' के तीसरे चरण में तमिलनाडु ने भारतीय मुद्रा रूपए का राष्ट्रीय चिन्ह बदलकर उसे तमिल वर्णमाला के अक्षर 'र' (रूपाई) में बदल दिया है। इसके पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके के हिंदी विरोध को राजनीतिक बताते हुए कहा था कि राज्य सरकार पहले वहां तमिल भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो व्यवस्था करे। शाह के इस आदेशात्मक 'सुझाव' से यह बहस फिर तेज हो गई है कि क्या देश में अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी व भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा संभव है, अगर है तो कैसे? हालांकि मप्र जैसे राज्य ने ढाई साल पहले मेडिकल की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करने की अच्छी पहल की थी। कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसकी शुरूआत हुई है, लेकिन यहां प्रश्न स्व-भाषा अभिमान और मातृ भाषा में सुगम शिक्षा से कहीं ज्यादा जटिल और व्यावहारिक चुनौतियों से भरा है। यह काफी हद तक सम्प्रेषण की एकरूपता से जुड़ा है एवं ग्लोबल भी है। दरअसल स्थानीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा का भविष्य उन छात्रों के भविष्य से तय होगा, जो इस माध्यम में पढ़कर निकले हैं। यह शिक्षा उन छात्रों के पेशेवर ज्ञान की अद्यतनता, प्रामाणिकता, कॅरियर और आजीविका से कितनी जुड़ पाती है तथा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र उनका कितना स्वीकार करते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर है। हकीकत में ऐसे नवाचारों को विद्यार्थियों के स्तर पर भी खास प्रतिसाद नहीं मिल पाया है। हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों की बहुत कमी है। जो अनुवाद हुए हैं, उनकी प्रामाणिकता तथा छात्रों की उनमें रूचि भी अहम है। ऐसी पुस्तकों को लेकर प्रकाशकों का रवैया भी बहुत उत्साहजनक नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में भी कुछ शिक्षा संस्थानों में तमिल में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन उसका प्रतिसाद लगभग वैसा ही है कि जैसे मप्र में हिंदी में इन विषयों की पढ़ाई को लेकर है। अव्वल तो बहुत ही गिने-चुने विद्यार्थी ही हिंदी या अन्य भारतीय भाषा को इन विषयों की पढ़ाई का माध्यम चुनते हैं, क्योंकि उनके लिए इस संदर्भ में स्वभाषा प्रेम से ज्यादा रोजगार की चिंता होती है। वर्तमान में देश के लगभग सभी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है। ऐसे में उनका आपसी संवाद भी बना रहता है। दूसरी तरफ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा माध्यम से पढ़कर आने वाले विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में विषय को समझना और आत्मसात करना कठिन होता है। उन्हें अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी होती है। कई बार मानसिक तनाव और कई बार न्यून ग्रंथि का शिकार भी होना पड़ता है।

हिंदी या मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पाने वाले बच्चों के सामने महाप्रश्न यह है कि डिग्री लेने के बाद उनका भविष्य क्या है? कौन उन्हें नौकरी देगा? क्या सरकारें ऐसे स्नातकों को आरक्षण देंगी? दो अलग-अलग माध्यमों से शिक्षित डॉक्टरों और इंजीनियरों में आपसी तालमेल कैसे बैठेगा? हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़े डॉक्टर, इंजीनियरों को कहीं तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से दोयम तो नहीं मान लिया जाएगा? अगर नौकरी मिल भी गई तो इन विषयों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध और अद्यतन ज्ञान उन्हें अपनी भाषा में कैसे, कब और कितना मिलेगा? यहां तक कि हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में उनकी मार्क शीट भी कितने लोग समझेंगे? यूं भी कारपोरेट में हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए कोई जगह नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और उससे सम्बद्ध कुछ कॉलेजों तथा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तिरूनेलवेली में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में होती है। राज्य सरकार भी तमिल में पढ़े इंजीनियरों में से 20 फीसदी को नौकरी में प्राथमिकता देती है। लेकिन वहां भी तमिल में इंजीनियरिंग पढ़ने को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई देता, क्योंकि निजी कंपनियां ऐसे इंजीनियरों को नौकरी देने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं रहतीं। क्योंकि उन्हें ऐसे छात्रों के इंजीनियरिंग ज्ञान के परफेक्शन पर संदेह रहता है। उधर विद्यार्थियों को लगता है कि क्षेत्रीय भाषा का अभिमान अपनी जगह है, लेकिन भारत में रोजगार जगत इसकी कोई खास वक्त नहीं है। इसके अलावा तकनीकी शब्दावली का तमिल या अन्य क्षेत्रीय भाषा में ठीक से अनुवाद उपलब्ध न होना भी है। कुछेक मामलों में मेडिकल की पढ़ाई भी तमिल में करने की प्रायोगिक सुविधा है। लेकिन छात्रों के सामने बड़ी कठिनाई तमिल में तकनीकी किताबों का अभाव है। यही वजह है कि क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली सीटों पर अधिकांश छात्र प्रवेश नहीं लेते। यूपी, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि का अनुभव भी यही रहा है। एआईसीटीई का डाटा कहता है कि हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली इंजीनियरिंग की ज्यादातर सीटें खाली रहती हैं। वर्ष 2021-22 में ऐसी 80 फीसदी खाली रहीं तो 2022-23 यह आंकड़ा 53 फीसद रहा। देश में सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों को मिलाकर इंजीनियरिंग की 25 लाख सीटें हैं। तीन साल पहले देश के 22 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने कुल 2580 सीटें हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में इंजी पढ़ने वाले छात्रों को ऑफर की थीं। मप्र की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित मैनिट कॉलेज में 2023 में 150 छात्रों ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन बाद में 27 छात्र ही शेष रहे।

तो क्या अमित शाह का इशारा भी महज सियासी शगूफा ही है या फिर सरकार सचमुच भारतीय भाषाओं को तकनीकी ज्ञान का वाहक बनाने के लिए संकल्पित है? यह सही है कि जो बच्चे स्कूल स्तर पर हिंदी या अपनी मातृभाषा में पढ़कर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजो में आते हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई में काफी दिक्कत आती है। कई बार तो वे समझ ही नहीं पाते। इसीलिए ये सोचा गया कि मेडिकल व इंजी. की किताबें भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार की जाएं ताकि ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सकें। मध्यप्रदेश में पहली बार अक्टूबर 2022 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी माध्यम की किताबें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की थीं। तर्क यही था कि जब रूसी,जापानी, जर्मन,चीनी आदि भाषाओंमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं? क्यों हम अंग्रेजी पर ही निर्भर रहें। क्यों विदेशी भाषा का बोझ ढोते रहें?

दरअसल हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। अभी ऐसे शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होती है। ऐसे में देश के किसी भी कोने का डॉक्टर या इंजीनियरिंग तकनीकी रूप से एक दूसरे की बात समझता है, सम्प्रेषित कर सकता है। अगर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इन विषयों की पढ़ाई होगी तो वो एक-दूसरे से कैसे किस भाषा में संवाद करेंगे। मसलन तमिल माध्यम में पढ़ा छात्र उत्तर भारत के किसी डॉक्टर या इंजीनियर के कैसे बात कर सकेगा? मलयालम में बनी डीपीआर हिंदी माध्यम वाला कैसे समझेगा? क्या इन क्षेत्रों में इतना जोखिम उठाया जा सकता है? यानी हमे हर स्तर पर अनुवाद और एकरूपता की जरूरत होगी और वह हमेशा प्रामाणिक ही हो, यह जरूरी नहीं है। दूसरे, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कितनी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी? उनका आपसी संपर्क किस भाषा में होगा। अगर वहां अंग्रेजी की जगह हिंदी विकल्प दिया गया तो दक्षिण व अन्य गैर हिंदी भाषी राज्य उन पर हिंदी थोपने का आरोप लगा सकते हैं, जो तमिलनाडु में हो ही रहा है, इससे और नई समस्या पैदा होंगी। तमिल में शिक्षित मेडिकल प्रोफेसर उस राज्य के बाहर पढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकता। हालांकि हिंदी वालों के लिए कुछ ज्यादा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम वालों जितने नहीं। सबसे बड़ी समस्या इन विषयों के अद्यतन ज्ञान की भी है। दुनिया में इस विषयों से सम्बन्धित शोध पत्र अंग्रेजी में तुरंत अनुदित हो जाते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं तक पहुंचने में बहुत समय लगता है या फिर वो हो ही नहीं पाते। हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा वाला विद्यार्थी या डॉक्टर अथवा इंजीनियर नए शोधों के बारे में जल्दी कैसे जानेगा? उसे उन शोध पत्रों का अनुवाद दूसरी भाषा में होने तक कितना इंतजार करना पड़ेगा? इससे भी बड़ी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी संपर्क और संवाद की है। बेशक दुनिया में अंग्रेजी सबकी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी डेढ़ अरब लोग इसे बोल या समझ सकते हैं।

वैसे यह सवाल पहले अंडा या मुर्गी की तरह है। हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी विषय पढ़ाना शुरू ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। इसका इलाज यही है कि आ रही दिक्कतों का समाधान ढूंढा जाए लेकिन गुणवत्ता से किसी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। अनुवाद की कड़ियों को मजबूत किया जाए। उसे पूर्णतः विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाया जाए। यह बहुत कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं बशर्ते कि वैसी संकल्पशक्ति और साफ नीयत हो।

॥ मंदिरम् ॥

59

भद्रावती लक्ष्मी नरसिंह मंदिर

भद्रावती लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जिसे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है, जिसे होयसल शासक वीर सोमेश्वर ने बनवाया था। यह भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के भद्रावती में स्थित है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें तीन गर्भगृह हैं, एक वेणुगोपाल के लिए, एक लक्ष्मीनरसिंह के लिए और एक विष्णु-पुरोषोत्तम के लिए। यह अपनी वेसर वास्तुकला के साथ-साथ वैष्णववाद की किंवदंतियों और देवताओं, साथ ही शैववाद, शक्तिवाद और वैदिक देवताओं को दर्शाने वाली कलाकृतियों के लिए भी उल्लेखनीय है। गणेश, दक्षिणामूर्ति, भैरव, सरस्वती, ब्रह्मा, सूर्य, हरिहर (आधे शिव, आधे विष्णु) और अन्य की नक्काशी उल्लेखनीय है।

उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय में 'भारत' शब्द का इस्तेमाल होगा

सभी दस्तावेजों से इंडिया नाम हटेगा, यह प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय

उज्जैन (नप्र)। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेजों पर 'इंडिया' शब्द की जगह 'भारत' शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 'इंडिया' शब्द को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी और कैलेंडर सहित सभी जगह भारत शब्द का प्रयोग होगा।। इस फैसले के साथ, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो अपने आधिकारिक दस्तावेजों में 'भारत' शब्द का प्रयोग करेगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक कुलगुरु प्रो. विजय कुमार जे.सी. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य दीक्षांत समारोह की तैयारियों पर चर्चा करना था। देर शाम तक चली बैठक में कार्यपरिषद सदस्य गौरव धाकड़ ने विश्वविद्यालय में 'इंडिया' शब्द की जगह 'भारत' शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सहमति से पारित कर दिया। कार्यपरिषद सदस्य गौरव धाकड़ ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश की संस्कृति और पहचान से जुड़े हुए हैं। इसी दिशा में विश्वविद्यालय में भी 'भारत' शब्द को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रशासनिक दस्तावेजों, विद्यार्थियों की कॉपियों, कैलेंडर आदि में अब 'भारत' शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। बैठक में कार्यपरिषद सदस्य विश्वास व्यास, हरीश व्यास, सुमिना लिग्गा, डॉ. केशर सिंह चौहान, गीतांजलि चौरसिया और कुलसचिव डॉ. दिलीप सोनी उपस्थित थे।

31 मार्च को होगा दीक्षांत समारोह

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का पांचवां दीक्षांत समारोह 31 मार्च को सुबह 11 बजे कालिदास संस्कृत अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित किया जाएगा।

समारोह में शोधार्थियों और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली बैठक में वित्तीय वर्ष के आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किए जाएँगे।

संस्कृत से जोड़ने का प्रयास

कार्यपरिषद सदस्य धाकड़ के प्रस्ताव पर उज्जैन के नागरिकों को संस्कृत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, संस्कृत सीखने के इच्छुक लोगों के लिए विश्वविद्यालय से दक्ष विद्यार्थियों को शिक्षक के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर 'रिसोर्स पूल सिस्टम' विकसित किया है, जिसमें योग्य शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यक्ति इनका लाभ होम ट्यूटर के रूप में भी ले सकेंगे। इसके अलावा, समुदाय में जाकर संस्कृत कक्षाएँ आयोजित कर आमजन को संस्कृत सिखाने का प्रयास किया जाएगा।

अस्पताल के लेबर रूम में एसी फटा, आग, प्रसूति वार्ड से 56 महिलाओं और नवजातों को निकाला

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एसी फटने से आग लग गई। हादसा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के लेबर रूम में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे हुआ। लेबर रूम से सटे प्रसूति वार्ड में भी धुआं भर गया। आनन-फानन में खिड़कियां तोड़कर 56 महिला मरीजों को वार्ड से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सभी सुरक्षित हैं। मरीजों की शिफ्टिंग का काम रविवार सुबह 4 बजे तक चलता रहा। सूचना मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान भी मौके पर पहुंची। कमला राजा अस्पताल ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल समूह का हिस्सा है।

लेबर रूम में 16, वार्ड में 50 महिलाएं भर्ती थीं-अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों के परिजन के मुताबिक, ग्वालियर में अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती 16 मरीज और उनके नवजातों के लिए एसी चला रहे थे। अचानक एक एसी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। लेबर रूम से सटे वार्ड में 50 महिलाएं डिलीवरी के लिए भर्ती थीं।

जमीन के विवाद में केस हारने के बाद आरोपितों ने कर दी पति-पत्नी की हत्या

टीकमगढ़ (नप्र)। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के करोला गांव में पीट-पीटकर दंपती की हत्या की वारदात सामने आई है। सूचना मिलने पर एसपी मनोहर सिंह मंडलोई और एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई थी।

कही-सुनी

भारतमाला प्रोजेक्ट में भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मालामाल

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कहते हैं भारतमाला परियोजना के तहत अभनपुर से विशाखापट्नम तक बनने वाली सड़क के मुआवजे से भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मालामाल हो गए। भारतमाला परियोजना के तहत अभनपुर से विशाखापट्नम तक बनने वाली सड़क छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रप्रदेश को जोड़ने वाली है। बताते हैं भाजपा के एक नेता को इस प्रोजेक्ट से करीब सौ करोड़ का मुआवजा मिला है। भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी आजकल छत्तीसगढ़ में सुर्ख़ियों में है। मुआवजा बांटने के गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने एक अपर कलेक्टर, एक डिप्टी कलेक्टर समेत पांच लोगों को अब तक सस्पेंड कर दिया है और मामले की जाँच राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) से कराने का फैसला किया है। मामला राज्य विधानसभा में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, पर सरकार ने माना नहीं। मुआवजा वितरण का खेला कांग्रेस राज में हुआ, फिर भी कांग्रेस के नेता डॉ चरणदास महंत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग क्यों कर रहे हैं, यह चर्चा का विषय है। बताते हैं इस प्रोजेक्ट में मोटा मुआवजा पाने वाले भाजपा और कांग्रेस के नेता डॉ महंत के निशाने में हैं। महंत एक तीर से कई निशाना भी साधना चाहते हैं। भारतमाला परियोजना में मुआवजा वितरण को लेकर साल 2021 में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने प्रेस कांफ्रेंस ली थी और भाजपा के नेता और प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से शिकायत की थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत को राष्ट्रीय राजमार्ग की विजिलेंस शाखा को भेज दी। भारतमाला परियोजना में पूरी राशि भारत सरकार खर्च कर रही है। कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की विजिलेंस शाखा की रिपोर्ट के आधार पर नितिन गड़करी ने विष्णुदेव साय की सरकार को अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बताते हैं नितिन गड़करी संज्ञान नहीं लेते तो मामला आया-गया हो जाता। अब देखते हैं ईओडब्ल्यू क्या जाँच करती है और गड़बड़ी करने वालों को किस तरह दबोच पाती है, पर एक बात तो साफ़ हो गया कि इस कांड से छत्तीसगढ़ की नाक कट गई है और लोगों की लालच का इंतहा नहीं है।

मंत्री लखनलाल देवांगन रहेंगे या जाएंगे ?

कोरबा के भाजपा विधायक और राज्य के उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन इन दिनों मुसीबत में हैं। भाजपा की लाइन से बगावत कर कोरबा नगर निगम के सभापति बनने वाले नूतन सिंह ठाकुर को सार्वजनिक तौर से बधाई देकर उलझे श्री देवांगन को पहले भाजपा संगठन ने नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा, फिर जांच टीम बना दी। राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर है कि भाजपा ने अपने किसी मंत्री को अनुशासन के मामले में नोटिस जारी किया है। श्री देवांगन सरकार के अंग होने के साथ पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और कोरबा में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव जीतने वाले की पीठ थपथपा कर वे क्या संदेश देना चाहते थे, यह चर्चा का विषय है। बताते हैं कोरबा नगर निगम के सभापति के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नाता रहा है। एबीवीपी से जुड़े होने के कारण उनका उप मुख्यमंत्री अरुण साव से अच्छे संबंध हैं। चर्चा है कि हितानंद ने अपने अच्छे संबंधों के चलते ऊपर से अपना नाम फ़ाइनल करा लिया, पर न तो उन्हें कोरबा के भाजपा नेता चाह रहे थे और न ही भाजपा के पार्षद। इसको न तो रायपुर में बैठे बड़े पदाधिकारी महसूस कर पाए और न ही पर्यवेक्षक पुरंदर मिश्रा अंदाज लगा पाए। हितानंद की हार और नूतन सिंह की जीत से कोरबा के भाजपा नेताओं का दांव सफल हो गया,पर पार्टी की किरकिरी हो गई। कोरबा के भाजपा नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को ठेंगा बता दिया। अब प्रदेश के नेता नोटिस और जांच के बहाने सांप भाग जाने के बाद लाठी पीट रहे हैं। कहते हैं लखनलाल देवांगन से रायपुर के भाजपा नेता गुस्से में हैं। इस घटना के बाद चर्चा होने लगी है कि लखनलाल देवांगन का मंत्री पद बचेगा या जाएगा,पर कहते हैं लखनलाल देवांगन के भाग्य का फैसला तो दिल्ली से होना है। जरूर प्रदेश संगठन ने अनुशासनहीनता के लिए मंत्री को नोटिस जारी कर हिम्मत का काम तो किया है, साथ में एक नजीर बना दी है।

प्राइवेट अस्पतालों पर आयकर विभाग की नजर

कहा जाता रहा है कि कोरोना काल में रायपुर के प्राइवेट अस्पताल वाले मालामाल हो गए। कई अस्पतालों का कर्जा साफ़ हो गया, तो कई अस्पताल वाले नई बिल्डिंग तान लिए, पर अब प्राइवेट अस्पताल वालों पर आयकर विभाग की निगाह गई है। कहते हैं 10 मार्च को आयकर विभाग ने राजनांदगांव और रायपुर के एक-एक अस्पताल का सर्वे किया और भारी मात्रा में कर चोरी पकड़ी गई। बताते हैं रायपुर के अस्पताल में 45 करोड़ की हेराफेरी पाई गई। अब आयकर विभाग भारी टैक्स ठोंकने के फिराक में है। रायपुर का अस्पताल नामी-गिरामी है और पाश कालोनी में होने के कारण यहां रईस मरीजों की तादाद ज्यादा बताई जाती है। कई बड़ी कंपनियां भी अस्पताल के ग्राहक हैं। बताते हैं कि आयकर के सर्वे की जद में आए रायपुर के अस्पताल के संचालक ने कोरोना काल में इतना माल समेटा कि रायपुर के कचना इलाके में सितारा होटल तानने में लगा है। अब देखते हैं आयकर विभाग का अगला कदम किस अस्पताल पर पड़ता है या फिर यह पहला या आखिरी होता है।

पूर्व मुख्य सचिव ने बेची जमीन

कहते हैं छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्य सचिव ने एक बड़े समूह को अपनी जमीन बेची है। बताते हैं कि सौदा करीब 130 करोड़ में हुआ है। चर्चा है कि समूह द्वारा पूर्व मुख्य सचिव की जमीन पर माल बनाया जाएगा। वैसे पूर्व मुख्य सचिव के पास रायपुर शहर में काफी जमीन और मकान हैं। पूर्व मुख्य सचिव ने जीई रोड स्थित जमीन का बड़ा टुकड़ा बेचा है। पूर्व मुख्य सचिव द्वारा जमीन बेचने की बड़ी चर्चा है। खबर उड़ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव अपनी जमीनें बेच कर विदेश में बसने की तैयारी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव दिल्ली से तय होगा

माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का फैसला हो जाएगा। लगभग तय समझा जा रहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन का चयन हो जाएगा। इस कारण अप्रैल के पहले हफ्ते में राज्य को नया मुख्य सचिव मिल जाएगा। बताते हैं कि नए मुख्य सचिव के लिए अमित अग्रवाल, सुब्रत साहू और मनोज पिंगुआ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सुब्रत साहू कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री के एसीएस रह चुके हैं। खबर है कि सुब्रत साहू के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाजपा नेता वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ़ है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव का फैसला दिल्ली से होगा।

भूपेश बघेल पर ईडी का साया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आखिरकार ईडी की जद में आ गए। पिछले दिनों ईडी ने उनके निवास पर धावा बोला। ईडी के निशाने पर भूपेश बघेल के बेटे और उनके समर्थक भी आ गए। कहते हैं भूपेश बघेल पर ईडी का साया मंडराता रहेगा। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ही लग रहा था कि भूपेश बघेल ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। ऐसी खबर है कि ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने जैसे कदम अभी नहीं उठाएगी। इसके लिए वह वक्त का इंतजार करेगी।

अब पुलिस अफसर निशाने पर

चर्चा है कि शराब घोटाले और महादेव सट्टा मामले में भूपेश बघेल को निशाने पर लेने के बाद अब ईडी महादेव सट्टा प्रकरण में कांग्रेस राज में सुर्ख़ियों में रहे पुलिस अफसरों को निशाने पर ले सकती है। खबर है कि पुलिस अफसरों को सरकार के कुछ ताकतवर लोग बचाने की मुहिम में लगे हैं, पर भूपेश बघेल की सरकार में हांसिये पर गए अफसर और नेता कांग्रेस राज के रणनीतिकारों के पीछे पड़ गए हैं और ईडी के मददगार भी बन गए हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मार्च की छत्तीसगढ़ यात्रा के बाद कुछ धमाका होगा।